हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

06 मार्च, 2017

खण्ड–1, अंक–7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 6 मार्च, 2017

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	3
सांसद तथा वित्त मंत्री, हरियाणा के सम्बन्धियों का अभिनंदन	3
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	3
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फिरोजपुर कलां, जिला फरीदाबाद के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन	21
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	21
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	37
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	40
मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा	57
वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	58

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 6 मार्च, 2017

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

शोक–प्रस्ताव

11:00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक–प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : स्पीकर सर, यह सदन नायक दिनेश कुमार, गांव जाडरा, जिला रेवाड़ी के पहली मार्च, 2017 को हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है तथा शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की चाची श्रीमती चन्द्रो देवी के 04 मार्च, 2017 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है तथा शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो शोक–प्रस्ताव सदन में रखा है मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ते हुए अपनी संवेदनायें प्रकट करता हूं तथा मैं इस सदन की भावनायें शोक–संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा ।

अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया ।)

.....

सांसद तथा वित्त मंत्री, हरियाणा के सम्बधियों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आज स्पीकर गैलरी में भारतीय जनता पार्टी के अम्बाला लोक सभा क्षेत्र से सांसद श्री रतन लाल कटारिया जी एवं हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, जो आज बजट प्रस्तुत करेंगे, उनकी धर्मपत्नी डॉ. श्रीमती अंकिता व भाई मेजर सत्यपाल सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी. ई. पी. गैलरी में मौजूद हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका यहां आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं उनके उज्ज्वल भविष्य व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

To Grant Pension to the Widower

***1939.Sh Ravinder Machhrouli.** : Will the Social Justice & Empowerment Minister be pleased to state whether there is any

proposal under consideration of the Government to grant pension to the widower on the pattern of widow pension togetherwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : जी नहीं, श्रीमान्

श्री रवीन्द्र मछरौली : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि नहीं पैंशन होगी और सरकार द्वारा इस बारे में न ही कोई विचार किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ताऊ देवी लाल जी ने बुजुर्गों की पैंशन 100/– रूपये प्रति माह शुरू की थी से वह चाहे भविष्य में बढ़कर 5000/– रूपये प्रति महीना हो जाए लेकिन बुजुर्ग सदा ही यह कहेंगे कि ताउ देवी लाल जी ने यह पैंशन शुरू की थी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर हमारी सरकार यह काम करती है अर्थात विधवा महिलाओं की तरह विधुर की पैंशन लागू करती है तो हमारी सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला होगा और लोगों द्वारा इसे सदा याद रखा जायेगा। यह एक प्रकार से विधुर वर्ग के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है क्योंकि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वह अपने बच्चों का पालन–पोषण करती है ठीक उसी प्रकार से ही जिस पुरूष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह विधुर हो जाता है तो उसको भी अपने बच्चों का पालन–पोषण करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक और गम्भीरतापूर्वक विचार करके विधुर पैंशन हर हाल में शुरू करें। यह एक बहुत अच्छी और सार्थक पहल होगी जिसका समाज के विधुर वर्ग में बहुत ही अच्छा मैसेज जायेगा। मैं यहां यह बात भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं को इस प्रकार की पैंशन से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नही है। इसलिए अगर वे यह फैसला कर देते हैं तो वे विधुर लोगों के दिलों में सदा–सदा के लिए विराजमान हो जायेंगे। लोग उनके सदियों तक गुण गायेंगे।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, सरकार का यह विचार बन रहा है कि हम अगले वित्तीय वर्ष से विधुर व्यक्तियों के लिए पैंशन की शुरूआत विधवा महिलाओं के पैटर्न पर कर देंगे।

श्री रवीन्द्र मछरौली : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने यह काम अपने लिए न करके पूरे प्रदेश के विधुर वर्गों के लिए किया है। मैं पूरे प्रदेश, पूरे विधुर वर्ग और अपनी तरफ से उनका उनकी इस दरियादिली के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। विधुर

वर्ग के लोग उनके नाम को सदा याद रखेंगे कि श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में उनकी पैंशन शुरू की थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बार–बार धन्यवाद।

———

Mahila Police Stations in Haryana

***1960 Smt Geeta Bhukkal. :** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of Mahila Police Stations set up in the state till to date;

(b) the sanctioned strength of women staff for a Mahila Police Station togetherwith staff deployed in each Mahila Police Station;

(c) the difference in the functioning of Mahila Police Stations and other police stations;

(d) the Police Station wise case registered, solved and challans, produced in the courts?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

सूचना

(क) राज्य में अब तक 22 महिला पुलिस थाने स्थापित किये जा चुके हैं।

(ख) एक महिला पुलिस थाना के लिए महिला पुलिस कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या व प्रत्येक महिला पुलिस थाना में नियुक्त महिला पुलिस कर्मचारियों की संख्या निन्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	जिला	स्वीकृत बल	तेनात बळ
1	पंचकुला	64	22
2	अम्बाला	64	39
3	यमुनानगर	79	37
4	कुरुक्षेत्र	79	25
5	कैथल	64	32
6	करनाल	97	31
7	पानीपत	79	26
8	जींद	64	64
9	हिसार	97	39
10	फतेहाबाद	64	27
11	सिरसा	64	29

12	**गुरुग्राम**	99	36
13	**फरीदाबाद**	99	47
14	**पलवल**	79	29
15	**मेवात**	64	12
16	**रेवाड़ी**	79	30
17	**नारनौल**	64	22
18	**रोहतक**	97	56
19	**झज्जर**	64	49
20	**भिवानी**	79	14
21	**सोनीपत**	79	26
22	**खान पुर सोनीपत**	22	9
कुल	**1640**	**701**	

ग) महिला पुलिस थाना व अन्य थाना की कार्यषाली में अन्तर :–

1. एक महिला पुलिस थानों का कार्यक्षेत्र हरियाणा सरकार के निर्देष संख्या एस. ओ140/1974/एस.2/2012, एस.ओ141/1974/एस.2/2012, एस. ओ142/1974/एस.2/2012, अनुसार पूर्ण जिले के तौर पर निर्देषित किया गया है जबकि अन्य पुलिस थानों का जिला में सीमित कार्यक्षेत्र होता है।
2. महिला पुलिस थानों में पूर्ण रूप से महिला पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाती है व उनकी सहायता व अन्य सेवाओ के लिए सीमित संख्या में पुरूष कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।
3. महिलाओं के विरूद्ध घटने वाले अपराधों व शिकायतों का निपटारा महिला पुलिस जांच अधिकारी द्वारा किया जाता है जो कि संवेदनषील एवं करूणा पूर्वक व्यवहार करने में प्रशिक्षित है। महिला पुलिस थानों की स्थापना महिलाओं को अनूकुल वातावरण एवमं जाच अधिकारियों का इस बात के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि वे पीडित महिला को प्रोत्साहन दें ताकि वह अपनी शिकायत दे और शिकायत का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करें।
4. जिलों में महिलाओं की सहायता के लिए एक चार अंकीय महिला हैल्पलाईन नम्बर 1091 सक्रिय है जो शिकायत दर्ज करने और पीडिता को अपनी शिकायत के निपटारे के लिए पुलिस की सहायता हेतू सुझाव देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।
5. सभी महिला पुलिस थानों में घरेलू उत्पीडन, पारिवारिक विवाद, दहेज की मांग आदि से सम्बन्धित शिकायतों के निपटारे के लिए एक परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक कुल 36,086

शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन में से 33,043 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

6. महिलाओं और बच्चों के लिए जिला स्तरीय विशेष सैल प्रत्येक महिला पुलिस थाना में स्थापित की गई है। इस सैल में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक महिला अधिकारी को घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 व बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत निषेध–एवं–संरक्षण तथा बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. प्रत्येक महिला पुलिस थानों में उत्पीडन का सामना करने वाली पीडिता के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता व सलाह हेतू हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक महिला अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है ।

8. सभी महिला पुलिस थाना में छेडछाड सम्बन्धी घटनाओं पर रोक लगाने हेतू छेडछाड विरोधी स्टाफ का गठन किया गया है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इनकी तैनाती स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, टयूशन/कोचिग केन्द्रों, बाजारों, शापिंग माल आदि जगहों पर की जा रही है।

(घ) महिला पुलिस थानों में पंजीकृत मुकदमों की संख्या, हल किये गये मुकदमों की संख्या व न्यायालय में भेजे गये मुकदमों की संख्या, निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक 28.08.2015 से 15.02.2017 तक महिला पुलिस थानों में पंजीकृत मामलों की संख्या, निपटारा एवं अदालत में भेजे गए मुकदमों की संख्या ।

क्रम संख्या	जिला	मामले पंजीकृत	मामलो का निपटारा	अदालत में भेजे गए मुकदमों की संख्या
1	पंचकुला	100	76	56
2	अम्बाला	230	177	137
3	यमुनानगर	148	125	84
4	कुरुक्षेत्र	71	62	37
5	कैथल	137	128	92
6	करनाल	220	192	124
7	पानीपत	99	88	47
8	जींद	129	117	92
9	हिसार	131	106	72
10	फतेहाबाद	172	163	113
11	सिरसा	74	64	47
12	गुरुग्राम	348	251	193

13	**फरीदाबाद**	265	204	171
14	**पलवल**	203	177	106
15	**मेवात**	128	102	57
16	**रेवाड़ी**	154	130	112
17	**नारनौल**	137	124	59
18	**रोहतक**	124	108	69
19	**झज्जर**	209	186	133
20	**भिवानी**	199	181	143
21	**सोनीपत**	205	188	145
कुल	**3483**	**2949**	**2089**	

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी ने पूछा है कि प्रदेश में महिला पुलिस थानों की संख्या कितनी है इस बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 22 महिला पुलिस थाने हैं । सोनीपत में 2 हैं और दादरी में अभी तक नहीं खोला गया है । हर जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाने खोले गये हैं । सितम्बर, 2016 में प्रदेश में पहली बार महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई थी । हरियाणा को बने 50 वर्ष हो गये हैं और हम हरियाणा की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तथा पहली बार हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थानों की स्थापना की है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । मैं मंत्री से कहना चाहती हूं कि इन अधिकारियों के बीच में Jurisdictional conflict है । सदन के पटल पर बहुत सारी सूचना उपलब्ध है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि आपने केवल जिला मुख्यालय पर ही महिला पुलिस थाने खोले हुये हैं। क्या कोई महिला अन्य सामान्य थाने में भी शिकायत दे सकती है या नहीं ? और अगर दे सकती है तो उसको महिला पुलिस थाने में ट्रांसफर करने की क्या प्रक्रिया है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि इन महिला पुलिस थानों में स्टाफ की क्या पोजीशन है? जो सूचना सदन के पटल पर रखी गई है उसके मुताबिक 40 प्रतिशत पद रिक्त दिखाये गये हैं तो उक्त पोजीशन में महिला पुलिस थाने किस प्रकार अच्छी तरह से काम कर पायेंगे ? जवाब में ज्यादातर स्टाफ पोजीशन खाली दिखाई गई है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इन थानों में स्टाफ के पदों को किस प्रकार से बाइफरकेट किया गया है यानी कितने सब–इन्सपैक्टर हैं, कितने

इन्सपैक्टर हैं या ज्यादातर महिला पुलिस कांस्टेबल के सहारे ही ये पुलिस थाने चल रहे हैं?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में महिला पुलिस अधिकारी 7 प्रतिशत हैं और हरियाणा में 45 हजार पुलिस फोर्स में से 3204 महिला पुलिस अधिकारी/कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं । 1032 महिला पुलिस कांस्टेबल्स के पदों पर भर्ती करने के लिए हमने विज्ञापन जारी किया है । हमारी सरकार आने के बाद हमने 830 महिला कांस्टेबल्स की भर्ती की है और वे ट्रेनिंग ले रही हैं । अध्यक्ष महोदय, बहन गीता भुक्कल जी ने पूछा है कि महिला थानों की ज्यूरिसडिक्शन क्या है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये महिला पुलिस थाने बनाये ही इसलिए गये थे कि वहां पर स्पेसिफिक केस दर्ज हो सकें । वहां पर महिला पुलिस एस.एच.ओ. हैं, महिला पुलिस डी.एस.पी. हैं और एक ए.डी.जी.पी. रैंक का अधिकारी इन महिला पुलिस थानों के कार्य की देख–रेख करने के लिए नियुक्त किया गया है । ये महिला पुलिस थाने केवल महिला उत्पीड़न और बच्चों से संबंधित मामलों को देखते हैं । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने हर जिले में प्रोटक्शन ऑफिसर की भी नियुक्ति की हुई है । इन महिला पुलिस थानों में हमारे स्पेसिफिक अधिकारी काउंसलिंग पर ज्यादा जोर देते हैं । इन थानों में आम तौर पर महिला उत्पीड़न और पति–पत्नी विवाद से संबंधित मामले ज्यादा आते हैं । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं असहाय होती हैं उनको हम लीगल ऐड भी देते हैं । विशेष तौर पर यह काम करना तो चाहिए था पिछली कांग्रेस सरकार को लेकिन ये नहीं कर पाये और हमने यह काम किया है इसलिए बहन गीता भुक्कल को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । मंत्री जी ने बताया है जिला मुख्यालय पर हमने एक ए.डी.जी.पी. रैंक का अधिकारी लगाया है । मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जिला स्तर पर स्टाफ की पोजीशन क्या है और सरकार जो महिला पुलिस की भर्ती करने जा रही है उसमें क्या केवल महिला कांस्टेबल्स की ही भर्ती की जायेगी ? क्या महिला कॉस्टेबल के सहारे ही महिला थाने चलेंगे ? जब हर जगह महिलाएं ही हमें बचा रही हैं तो क्या उनको फाईनैंशियल स्पोर्ट की जरूरत नहीं है ? ऐसी बहुत सी सशक्त महिलाएं भी हैं जिनके मामले महिला पुलिस स्टेशनों में होंगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि आपने जो ये महिला कॉस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की है उसको

कितने समय में पूरा किया जाएगा ? हमारी सरकार के समय में हम भर्ती प्रक्रिया पूरी करके गये थे केवल रिजल्ट घोषित करना बाकी था । लेकिन उसको आपकी सरकार ने रद्द कर दिया था । इसके साथ ही मैं यह जानना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने हर जिले में प्रौटैक्शन एण्ड प्रौहिबिशन ऑफिसर्ज को महिला थानों में लगाया हुआ है । ये जितनी भी प्रौटैक्शन एण्ड प्रौहिबिशन ऑफिसर्ज लगाई हुई हैं उनको सरकार ने केवल मात्र कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाया हुआ है और उनको केवल 20 हजार रूपये मासिक वेतन दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अगर सरकार महिलाओं के हकों को लेकर इतनी गम्भीर है तो क्या इन प्रोटैक्शन एण्ड प्रोहिबिशन ऑफिसर्ज की रेगुलर भर्ती की जाएगी ? इनमें ज्यादातर एम.एस.डब्ल्यू. और एल. एल.बी. हैं । इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार ने इनको कोई भी व्हीकल नहीं दिया हुआ है । मैं यह भी जानना चाहूंगी कि जो महिला पुलिस स्टेशन्ज हैं उनमें हमारी महिला ऑफिसर्ज को, कांस्टेबल को या हैड कांस्टेबल को क्या व्हीकल्ज दिये गये हैं और इसके साथ–साथ उनको क्या वैपन्ज दिये गये हैं ? यह बताया जाता है कि उनके पास तो डंडा भी नहीं है केवल एक स्कूटी है क्या उनको भी ए.के.47, मशीनगन या पिस्टल दी जाएगी ? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का बहुत बड़ा नारा देश और प्रदेश में चल रहा है उसका क्या औचित्य रह जाएगा ? क्या स्पेशल ड्राईव के तहत बेटियों के लिये पुलिस में भर्ती करने का कोई स्पेशल ड्राईव चलाया जाएगा क्योंकि स्टेट में जब केन्द्रीय मंत्री आई थी तो she was also not satisfied with the opening of the Mahila Police Stations in the State of Haryana. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहूंगी कि यह शुरूआत हम हमारी सरकार के समय में ही कर चुके थे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायिका श्रीमती गीता भुक्कल जी को बताना चाहता हूं कि महिला सब इंस्पैक्टर की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जिसमें 830 महिला पुलिस ट्रेनिंग कर रही हैं और यह रेगुलर भर्ती है यह कोई अस्थाई नहीं है। वह कोई कन्सोलिडेटिड तनख्वा पर नहीं हैं। हमने दो जिलों महेन्द्रगढ़ और करनाल में महिला कॉन्सिलिंग के लिये एक नया एक्सपैरीमैंट किया है कि पुलिस थानों और समाज के बीच में जो घरेलू डोमैस्टिक वायलैंस होती है उसकी सूचना प्रोटेक्शन एडं प्रोहिविशन आफिसर पुलिस स्टेशन

तक देगी। जहां तक बहन जी एफ.आई.आर. की बात कह रही हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हमारा एक पुलिस का पोर्टल है और इस पोर्टल पर कोई भी आदमी किसी भी समय अपनी एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है। जो महिला थानों से संबंधित एफ.आई.आर. हैं उसके लिये भी हमारा यह पोर्टल दिन रात काम करता है। बहन जी का तो ऐसा ही काम है । अध्यक्ष महोदय, हम तो मेहनत करके आते हैं लेकिन वह एक मिनट में कह देती हैं कि I am not satisfied with the answer. बहन जी, यह तो आपका प्रोरोग्रेटिव है सैटिसफाई होना न होना आपकी मर्जी पर निर्भर है । परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब से हमने महिला थाने खोले हैं तब से उनमें 3483 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं । इन्हीं थानों के माध्यम से 2949 केसों का निपटारा किया गया और 2089 एफ.आई. आर. का हमने चालान पुटअप किया है । None FIR is pending क्योंकि या तो उनका निपटारा हो गया है या उनका चालान पुटअप हो गया है । स्पीकर सर, पीछे की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया। बी.जे.पी का तो हरियाणा में सरकार चलाने का पहला अनुभव है । हम माननीय श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में नये–नये प्रयोग प्रारम्भ कर रहे हैं। हमने महिला थानों का जो प्रावधान किया है उसके लिये गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने भी हमको बधाई दी है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहा है कि महिला कॉस्टेबलों के लिये क्या वैपन्ज दिये जा रहे हैं और उनको व्हीकल्ज की क्या सुविधा दी गई है तथा जो प्रौटैक्शन एण्ड प्रौहिबिशन ऑफिसर्ज लगाई हुई हैं उनकी केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्ति की हुई है उनको रेगुलर क्यों नहीं किया गया ? यह अच्छी बात है महेन्द्रगढ़ जिला आपका है और करनाल जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का है । वहां पर आपने कुछ स्पैशल तैयारी कर ली है लेकिन पूरे हरियाणा की विकास की बात होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मेरे जो प्रश्न हैं उनका जवाब नहीं आया है। आज भी अखबार में छपा है कि जिला पानीपत के महिला पुलिस स्टेशन में प्रौटैक्शन ऑफिसर और महिला पुलिस स्टेशन की एस. एच.ओ. के बीच डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से एस.एच.ओ. का ट्रांसफर कर दिया गया। अतः इन परिस्थितियों के मद्देनज़र मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि चूंकि प्रौटैक्शन ऑफिसर्ज व प्रोहिबिशन ऑफिसर्ज की टैम्परेरी नियुक्ति की जाती है, इसके अतिरिक्त इनको किसी प्रकार के कोई व्हीकल्ज भी प्रोवाइड नहीं करवाये

जाते तो ऐसी हालत में इनको सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करने की जरूरत है ताकि यह अच्छे तरीके से महिलाओं की सुरक्षा व समस्याओं को सुलझाने में अहम रोल अदा कर सकें? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गीता जी, माननीय मंत्री ने सब कुछ क्लीयर तो कर ही दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में एफ.आई. आर. की ज्यादा बात की है और मेरे द्वारा उठाये गए प्रश्न को घुमाकर जलेबी की तरह बना दिया है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई 1091 हैल्प लाईन जोकि पूरे देश में कार्यरत है, को हमारी सरकार के समय में ही बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न का आश्य यह है कि प्रौटैक्शन या प्रौहिबिशन आफिसर्ज की कांट्रैक्ट आधारित नियुक्ति को रेगुलर करने, व्हीकल्ज तथा वेपन मुहैया करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या इन्हें खाली हाथ ही महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल है और प्रश्न काल के सीमित समय में किसी एक सदस्या को बोलने के लिए इतना समय देने का मतलब यह है कि दूसरे सदस्यों को अपने प्रश्नों को पूछने के लिए कोई समय नहीं मिलेगा। गीता जी को तो माइक मिलना चाहिए उसके बाद इनका माइक छोड़ने का दिल ही नहीं करता है। जितना समय गीता जी को बोलते हुए हो गया है इतने समय में तो दो सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछे जा सकते थे।(शोर एवं व्यवधान) पता नहीं कांग्रेस वालों को क्या ट्रेनिंग दे रखी है?

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मुझे दया की जरूरत नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, मंत्री जी ने दया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सदन में एक महिला को प्रश्न पूछने से रोका जा रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उदय भानः अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इस विषय को लेकर कोई महिला सदस्य अपनी बात रखना चाह रही है तो उसको अपनी बात रखने का मौका जरूर देना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि पुलिस में भर्ती हो रही है। अतः आप अब बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी ने जो उत्तर सदन के समक्ष रखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कितने केस दर्ज हुए, कितनों के निपटारे हुए और कितने चालान हुए। (शोर एवं व्यवधान) आपके प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी से सभी चीजें बता दी गई हैं। अब सब कुछ साफ हो गया अतः आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, प्रौटैक्शन ऑफिसर्ज और प्रौहिबिशन ऑफिसर्ज की नियुक्ति कांट्रैक्ट आधारित है क्या इनको रेगुलर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? मैंने जो सवाल पूछा था उसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। मंत्री जी मेरे मूल प्रश्न वाले ट्रैक से अलग होकर एफ.आई. आर. के बारे में ही बताने लग गए है। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी ने प्रौटैक्शन एंड प्रौहिबिशन आफिसर की नियुक्ति संबंधी प्रश्न किया है। वास्तव में जो मूल प्रश्न है वह पुलिस विभाग से संबंध रखता है लेकिन चूंकि प्रौटैक्शन एंड प्रौहिबिशन आफिसर्ज का संबंध महिला एवं बाल विकास विभाग से है तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगी कि प्रौटैक्शन एंड प्रौहिबिशन आफिसर्ज की नियुक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जाती है। माननीय सदस्या द्वारा पूछा गया यह एक सैपरेट प्रश्न है इसलिए मैं इस संदर्भ में केवल इतना ही बताना चाहूंगी कि प्रौटैक्शन एंड प्रौहिबिशन आफिसर्ज की कांट्रैक्ट आधारित नियुक्ति का प्रावधान पहले की सरकारों के समय से रहा है, इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी यदि माननीय सदस्या लेना चाहती हैं तो वह लिखकर दे दें उसका जवाब जरूर दिया जायेगा। वैसे मैं इस संबंध में यह भी बताना चाहूंगी कि महिला पुलिस थाने में कुछ मामले घरेलू हिंसा तथा आपसी मनमुटाव के आते हैं तो ऐसी अवस्था में प्रौटैक्शन ऑफिसर्ज तथा प्रौहिबिशन आफिसर्ज का यह दायित्व होता है कि वह उनको काउंसलिंग के माध्यम से समझाकर विवाद को खत्म करवाये ताकि परिवार और समाज के अंतर्गत दूरिया न पनपे और परिवार न बंटे। इसके अतिरिक्त जैसाकि बहन गीता जी ने प्रश्न किया

है तो मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगी कि जहां कही पर भी इनको स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी, निःसेदह उस दिशा में जरूर कार्य किया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि प्रौटैक्शन ऑफिसर्ज व प्रौहिबिशन ऑफिसर्ज की नियुक्ति हमारे कांग्रेस सरकार के समय से होती रही है, अब जो चीज हमारे समय से चल रही है उसको कम से कम स्ट्रैंथन करने का काम तो सरकार द्वारा किया ही जाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, मंत्री जी ने यह कहा कि आपके समय में इनको कांट्रैक्ट पर रखने का काम किया गया था, उन्होंने यह नहीं कहा कि आपकी सरकार ने यह काम शुरू किया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, गीता भुक्कल जी हर बात का क्रेडिट अपनी सरकार को देना चाहती है जो कुछ अच्छा हुआ वह इनकी सरकार के समय में ही हुआ लेकिन इन्होंने अब मुझे इनकी सरकार की वास्तविकताओं के बारे में बताने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के शासन काल में महिलाओं के साथ किस–किस तरह के अपराध होते थे। रोहतक का अपना घर कांड मैं समझती हूँ कि आज भी प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ एक धब्बा है, काला अध्याय है। (शेम शेम की आवाजें)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, रोहतक के इस अपना घर कांड में छोटी–छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करवाया जाता था और अपना घर चलाने वाली महिला ने अपने दामाद के साथ मिलकर जिस तरह का कांग्रेस की सरकार के लोगों से इन बच्चियों का उत्पीड़न करवाया था, वह बात किसी से छिपी नहीं है। मैं समझती हूँ कि इनको उस कांड के बारे में भी सदन में बताना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, अब आपने जब प्रश्न किया है तो मंत्री तो जवाब देंगी ही?(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन काल में सरिता कांड हुआ, पंचकुला में ज्योति मर्डर केस कांड हुआ, मिर्चपुर में दलित महिला के घर पर आग लगाई गई थी तथा उसके पिता को जिंदा जलाया गया। अध्यक्ष महोदय, इनको इन कांडों के बारे में भी सदन को बताना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार

महिलाओं के अपराधों के खिलाफ निपटने के लिए पूरी तरह से गम्भीर है और निःसंदेह महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए नई महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायेगी और इनको स्ट्रैंथन करने के हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, शायद गीता जी को उनके प्रश्न का जवाब मिल गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, यह घरेलू हिंसा से संबंधित मामला है और इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि 50 परसेंट मामले सोल्व कर दिये गए हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है उसका सही जवाब नहीं आया है । These Protection and Prohibition Officers are going to sit in the Mahila Police Stations. माननीय मुख्य मंत्री जी ने परसों ही इस संबंध में कहा है और उन्होंने इससे पहले भी मीटिंग ली है । माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि this is a seperate question. मुझे हैरानी है कि प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कैसे कह सकती हैं कि महिला थानों में प्रौटैक्शन एंड प्रौहिबिशन ऑफिसर्स का मामला सैपरेट है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, यह क्वैश्चन सैप्रेट इसलिए है चूंकि महिला प्रोटैक्शन पुलिस ऑफिसर के बारे में जो भी फैसला लिया जाएगा वह महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लिया जाएगा ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष जी, इन महिला पुलिस थानों की स्थापना करने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक इनका ठीक से संचालन नहीं किया जाता है । (शोर एवं व्यवधान)

Construction of Four- Laned Bridge

***1953 Sh. Mool Chand Sharma.** : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Four-Lane Bridge on Ballabgarh Railway Line which connects Sohna and Ballabgarh the announcement of which was made by the

Hon'ble Chief Minister on 6th February 2016; if so, the time by which its construction work is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां सर। समय केवल भूमि के प्रबंध के बाद ही बताया जा सकता है।

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सोहना से बल्लभगढ़ जाने वाले फ्लाईओवर के बीच में दो फैक्ट्रियां आती हैं । इन दोनों फैक्टरियों से 20–20 मीटर जगह ली जानी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जमीन एक्वायर करने के संबंध में उन फैक्टरी मालिकों से विभाग के अधिकारियों की या किसी कमेटी की मीटिंग हुई है ? वह फैक्टरी छाँयसा गांव में शिफ्ट हो चुकी है और इस जमीन का कुछ हिस्सा स्टायर वायर फैक्टरी के अंतर्गत आता है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मंझावली का जो पुल बनाना मंजूर हुआ है वह माननीय सदस्य श्री ललित नागर के विधान सभा क्षेत्र में आता है । हमारे क्षेत्र में दो पुल नीलम और बड़खल हैं । यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी की रैली में मैंने और माननीय सदस्य श्री नागेन्द्र भड़ाना ने इनका विषय उठाया था । वहां पर बहुत–सी फैक्टरियां लगी हुई हैं और इनका सारा माल यहीं से होकर जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बजट में इनके लिए कोई प्रावधान किया गया है ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी रैली के दौरान सोहना, ग्रेटर नोएडा, मंझावली और रिवाड़ी को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की घोषणा की थी । इस पुल के अलावा इन क्षेत्रों को जोड़ने वाला कोई अन्य पुल नहीं है । अतः यह बहुत सीरियस मैटर है । हरियाणा सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिनांक 6 फरवरी, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के संबंध में बजट में क्या प्रावधान किया गया है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सोहना–बल्लभगढ़ मार्ग पर ऑलरेडी दो मार्गी पुल बना हुआ है । इस मार्ग पर थोड़ी–सी भीड़ रहती है । अब हम इसे चारमार्गी करने की कोशिश कर रहे हैं । वहां पर कुछ जगह पर सरकारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और कुछ जगह कमर्शियल हैं । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम डी.सी. की अध्यक्षता में एक कमेटी बना देंगे जिसमें माननीय विधायक जी भी इसके सदस्य

होंगे । यह कमेटी फैक्टरी मालिकों के साथ बैठकर जमीन के रेट तय कर लेगी । इसके बाद हम जमीन अधिग्रहण करके उस मार्ग को चारमार्गी कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या – 1958

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री हरि चन्द मिड्ढा सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

Supply of Drinking Water

***1728.Sh. Jaiveer Singh . :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that the water supply work in village Khanda, Sehri, Cholka (Sonepat) was in progress during the year 2013 is lying stalled since the November, 2014; if so, the time by which the work on the scheme for drinking water is likely to be started by the Government?

जन स्वास्थय अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) : श्रीमान् जी, तीन गांवों की खांडा समूह के लिए जल आपूर्ति का कार्य 05.04.2013 को अलाट किया गया था। कई बार अनुरोध करने के बाद भी एजैंसी द्वारा कार्य पूरा नहीं किया गया। एजैंसी के विरुद्ध अनुबन्ध के उपनियमों के अनुसार कार्यवाही की गई थी। शेष कार्य पहले वाली एजैंसी के जोखिम और लागत पर दूसरी एजैंसी को दिनांक 27.09.2016 को अलॉट किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है तथा इसके 30.06.2017 तक पूरा होने की संभावना है। अध्यक्ष जी, यह कार्य मार्च महीने तक पूरा किया जाना था । केंद्र सरकार से बजट प्राप्त न होने की वजह से इसमें डिले हुई और अब इसका निर्माण 30.6.2017 तक पूरा होने की संभावना है ।

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिये गए जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । माननीय मंत्री जी ने जो रियल चीज थी वह नहीं बताई है । मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन गांवों सेहरी, खांडा और चोलका में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक स्कीम बनाई थी । मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस स्कीम के लिए 4–5 साल पहले साढ़े तीन करोड़ रूपये मंजूर किये थे । उस स्कीम पर काम

पूरा हो चुका है । अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद काम बंद हो चुका है। माननीय मंत्री जी का जवाब बिल्कुल निराधार है और मैं इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। माननीय मंत्री जी सिर्फ यह बताएं कि इन तीन गांवों को कब तक पानी मिलेगा?

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इसके बारे में बता दिया गया है।

Construction Work of Guru Gobind Singh Marg

***1971. Sh Balkaur Shingh.** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of Guru Gobind Singh Marg passing through village Kewal, District Sirsa of Kalanwali Constituency is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, सड़क पहले से ही निर्मित और अच्छी स्थिति में है।

श्री बलकौर सिंहः अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में भी इस सड़क के बारे में चर्चा होती थी। यह सड़क गुरू गोबिन्द सिंह मार्ग के नाम से जानी जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क सिखों के बहुत बड़े धार्मिक स्थान तख्त साहिब श्री दमदमा साहिब को हरियाणा और राजस्थान से जोड़ती है। यह सड़क 100 किलोमीटर तक सिरसा जिले से गुजरती है। यह सड़क वहां पर 30 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे पर पड़ती है और 70 किलोमीटर का जो बाकी पोर्शन है वह खस्ता हालत में है। इस सड़क को बनाने के लिए मैंने माननीय मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि यह सड़क धार्मिक भावना के साथ भी जुड़ी हुई है और दो राज्यों को भी मिलाती है। इस सड़क की हालत काफी खराब है। पंजाब सरकार गुरू गोबिन्द सिंह मार्ग के नाम से बहुत बढ़िया सड़क पहले ही बना चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार भी 350 वां गुरू गोबिन्द सिंह जी का पर्व मना रही है। इस उद्देश्य से यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सड़क को जरूर बनाने की कृपा करें क्योंकि सिरसा जिला इसमें कवर होता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से अनुरोध है कि जो सड़क पहले से ही निर्मित है वह छोटी और अच्छी स्थिति में नहीं है इसलिए इस सड़क को चौड़ा करके अच्छी तरह से बनाया जाये।

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह गांव की 1.33 किलोमीटर की सड़क है और अच्छी स्थिति में है बाकी तकरीबन 95.59 किलोमीटर सड़क हरियाणा में से गुजरती है। बहुत सी सड़क इसमें चार लाइन और 18 फीट की और कुछ 21 फीट की भी है। अध्यक्ष महोदय, आगे आने वाले समय में जो 12 फीट की सड़क है उसे हम 18 फीट की करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर सड़क खराब है वहाँ ठीक करवा देंगे।

To Add Value to the Crops

***1974.Smt. Prem Lata.:** Will the Agriculture Minister be pleased to state: -

(a) the steps taken by the Agriculture Department to add value to the crops of the farmers; and

(b) whether the State Government has identified projects for value addition in coarse grains, edible oils and pulses togetherwith the details of projects ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) बागवानी विभाग, हरियाणा ने घरेलू स्तर पर संरक्षित और प्रसंस्कृत उत्पादों के रूप में बागवानी उत्पादों का मूल्य संवर्धन पर परिक्षण प्रदान करने के लिए 3 खाद्य प्रौद्योगिकी केन्द्र कुरूक्षेत्र, जीन्द और सिरसा में एक–एक की स्थापना की है। पिछले दो वर्षों के दौरान, 247 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें 5231 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

इसके अलावा, हैफेड ने 11 राईज़ मिल्स, एक चीनी मिल असंध में, दो सरसों तेल मिल्स नारनौल और रेवाड़ी में, एक फलोर मिल तरावड़ी में और दो पशु आहार संयत्र रोहतक और सकताखेड़ा (सिरसा) में लगाए हैं।

(ख) नहीं, श्रीमति जी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के प्रश्न के बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह व्यावसायिक स्तर पर नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों के

दौरान 247 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया था जिसमें आचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम बनाना, जैली बनाना, आदि हैं जिसमें 5231 प्रशिक्षुओं को इसमें प्रशिक्षण दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड का अबूब शहर में भी एक पैकेजिंग, ग्रेडिंग, शोर्टिंग और कोल्ड स्टोर हैं। लेकिन अब उसका टैंडर फिर से किया है ताकि कोई प्राईवेट पार्टी उसको फिर से चलाए जिससे किन्नू की खेती से किसानों को फायदा हो सके। अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग बोर्ड के अलावा यह प्रशिक्षण हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार में भी बाजरे की बिस्किट जैसे मोटे अनाजों से कई चीजें बनती हैं वहाँ भी शुरू किया है। इसके अलावा हैफेड ने 11 राईस मिल्स, एक चीनी मिल असंध में, दो सरसों तेल मिल्स नारनौल और रेवाड़ी में, एक फ्लोर मिल तरावड़ी में और दो पशु आहार संयत्र रोहतक और सकताखेड़ा (सिरसा) में लगाए हैं।

श्रीमती प्रेमलताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र उचाना में लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से 85 एकड़ में अनाज मण्डी बनने जा रही है। क्या इस अनाज मण्डी में किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए मूल्य संवर्धन करने के लिए कोई परियोजना सोची है? अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल मेरा यह है कि बधाना गांव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि होर्टिकल्चर का एक सैन्टर आ रहा है। उसमें जब फल और सब्जी पैदा होगी तो क्या उसके लिए भी मूल्य संवर्धन का कोई प्रावधान किया है? जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँच सके।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, अभी उचाना के बारे में स्पेसिफिक योजना के बारे कोई डिटेल नहीं है। परन्तु माननीय सदस्या के पास कोई सुझाव है तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हम हार्टिकल्चर के 140 सैंटर कलेक्शन बना रहे हैं तथा इसके लिए हमने 340 गांवों की पहचान कर ली है। उन कलेक्शन सैंटरों में सोरटिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग करने की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे किसानों को अलग–2 लेवल पर पैक करके ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके उसके लिए हमारा विभाग कार्य कर रहा है। हमारे प्रदेश में हार्टिकल्चर की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में है वहां पर सब तरह के प्रोजेक्ट हैं बल्कि हम इससे भी आगे बढकर प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन उचाना के लिए कोई स्पेसिफिक सुझाव है तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग दी

जा रही है। हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जब बन जायेगी तो उसके रिजनल सैंटर भी बनाये जाएंगे तथा हार्टिकल्चर के प्रोडेक्टस बनाने के लिए ट्रेनिंग सैंटर और डेमोसट्रेशन सैंटर भी इन सब स्थानों पर बनाये जायेंगे।

.....

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फिरोजपूर कलां, जिला फरीदाबाद के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, फिरोजपूर कलां, जिला फरीदाबाद के बच्चे और अध्यापक सदन की कार्यवाही देखने आएं हैं। यह महान सदन उनका स्वागत करता है।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्रीमती प्रेमलता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहती हूं कि क्या फलों की सोरटिंग करने का भी कोई प्रावधान है। जैसे किन्नू होता है उनका साईज छोटा और बड़ा होता है। उसी हिसाब से उनकी कीमत होती है। क्योंकि सैपरेट करने से किसानों को उसका सीधा लाभ हो सकता है। सभी फ्रुटस की यानी अमरूद बेर, संतरा, किन्नू की खेती किसान करता है। इसके अतिरिक्त फूलों की मंडी के बारे में भी पूछना चाहती हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश से कृषि विभाग के अधिकारी हालैंड के दौरे पर गये थे। उन्होंने वहां पर फूलों की मंडी का निरीक्षण किया था उस मंडी में आक्शन से चार घंटे में पूरी दुनिया के फूल बिक जाते हैं। क्या हमारी सरकार के पास किसानों के लिए ऐसी मंडी बनाने का कोई प्रावधान है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़: आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अबूब शहर में माकेर्टिंग बोर्ड की जो संस्था है उसमें सोरटिंग की व्यवस्था है। अलग–2 साईज के हिसाब से फलों की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे अधिकारी वहाँ इसलिए गये थे कि हम भी अपनी एक फूलों की मंडी गुरूग्राम में विकसित करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में गुरूग्राम, फरीदाबाद, फरूखनगर, पलवल व झज्जर का इलाका फूलों की खेती करता है हमारी सरकार किसानों के लिए एक अच्छी मंडी विकसित करना चाहती है, ताकि हमारे फूलों की खेती करने वाले किसानों को उसका लाभ मिल सके इसीलिए हमारी टीम वहां पर निरीक्षण के लिए गयी थी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब की बार आलू व मटर की फसल का बहुत ही कम भाव था।

आलू का भाव प्रति क्विटंल 100–150/– रूपये तथा मटर का भाव 300–400 रूपये प्रति क्विंटल था। ऐसे हालत में हमारी हैफेड की एजेंसी राईस की खरीद करके राईस सेलिंग का कार्य करती है। तो मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार चाहे कुटीर उद्योग हो या हैफेड की तरफ से कोई ऐसी बड़ी फैक्टरी लगाने जा रही है ताकि जब उत्पादन का भाव कम मिलता है तो उसको संभालने के लिए हैफेड की तरफ से खरीद कर सकें ताकि किसानों को फसल का उचित रेट मिल सकें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी चिन्ता का विषय है और कई बार आलू, गोभी, टमाटर व प्याज की फसल के दाम काफी कम होते हैं जिससे किसानों को लाभ न के बराबर होता है। आज माननीय वित्त मंत्री जी प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं इसके लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कोई ऐसा प्रावधान बजट में करें ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित रेट मिल और उन्हें लाभ हो सके।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी दादरी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से इसी से रिलेटिड सवाल पूछना चाहती हूं कि प्रदेश में कई स्थानों पर वाटर लॉगिंग हो रही हैं और हजारों एकड़ जमीन खराब हो चुकी है। क्या वाटर लॉगिंग को समाप्त करने के लिए सरकार कोई प्रावधान कर रही है ताकि किसान अपनी जमीन पर खेती कर सकें ?

श्री अध्यक्षः बहन जी, आप मूल सवाल से संबंधित ही अपना प्रश्न पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है तो डिफरेंट परन्तु अगर मंत्री जी इसका जबाव दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यह किसानों के हितों से संबंधित है।

श्री अध्यक्षः बहन जी, अगर आप कोई भी ऐसे अलग सवाल करेंगीं तो मंत्री जी जबाव कैसे देंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह दें कि it is not related. अगर वे कह देंगे कि it is not related तो मैं आगे सवाल नहीं पूछूंगी।

श्रीमती कविता जैन : आपका सवाल आ गया, आप शायद भूल गई हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखंड़ : अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारा इमलोटा का इलाका है, उसकी वास्तव में वहां समस्या है, और वह एक गंभीर समस्या है। हमारे मुख्यमंत्री

जी वहां गए थे, तभी उस पर सरकार काफी सारी चीजें करने के लिए आगे बढ़ी है।

To Set Up a Solid Waste Management Project

***1748. Smt. Kiran Choudhary. :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to State:-

(a) whether it is a fact that a revised Detailed Project Report (DPR) of worth Rs. 4.4 crore for setting up a Solid Waste Management Project at Bhiwani town under UIDSSMT has been forwarded vide Memo No. TA/DULB/2014/ 10567, dated 19.02.2014; and

(b) if so, the steps taken by the State Government for approval of aforesaid DPR and released of funds for this project ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री कविता जैन) :

(क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि जेएनएनयूआरएम योजना 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई थी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, मैं इस बारे में बहुत सारी चिट्ठियां उनको लिख चुकी हूं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रॉजेक्ट है और बी.जे.पी सरकार का एक स्टेलर प्रोग्राम है स्वच्छ भारत अभियान। भारत किस तरह से स्वच्छ हो सकता है, यह देखने की बात है क्योंकि सिर्फ झाड़ू लगाने से तो यह नहीं हो सकता। इस अभियान के द्वारा अगर आपको सही मायने में स्वच्छ भारत की वास्तविक रूप में पहचान बनानी है तो यह बहुत जरूरी है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, उसे हर जिले के अंदर लगाए जाए, वरना हमारा स्वच्छ भारत का काम पूरा नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि इसका 100 परसेंट सेग्रीगेशन नहीं होता है और सॉलिड वेस्ट की इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन होती है, रोड साइड पर डम्पिंग होती है, जिससे बहुत गंदगी फैलती है। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि वह 31 मार्च, 2014 को खत्म हो गया था। जब केन्द्र सरकार ने इसे मंजूर कर लिया

था और साढ़े 4 करोड़ रुपया यहां के लिए दे दिया था। हमने डी.पी.आर भी भेज दी थी तो उसके बावजूद 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उसके ऊपर केन्द्र सरकार से बात करके कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

श्रीमती कविता जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सम्मानित साथी को बताना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ से जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि उनके ही समय में हमारी प्रदेश सरकार ने 19.02.2014 को 4.4 करोड़ रुपए की एक योजना उस समय केन्द्र सरकार को भेजी थी। इसका मतलब यह होता है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। (विघ्न) आगे भी बताऊंगी, मैं आपको सारी बात क्लीयर कर दूंगी। मैंने जवाब दिया है कि 31 मार्च, 2014 को यह योजना समाप्त हो गयी थी। उस समय की केन्द्र की सरकार अपने पत्र दिनांक 18.07.2014 को अपने निर्णय से यह अवगत कराया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन द्वारा यह योजना 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो चुकी है और जो इन्होंने प्रपोजल भेजी वह इन्हीं की सरकार में भेजी गई थी और इन्हीं की सरकार के समय रद्द कर दी गई। आज यहां दूसरी बात आती है स्वच्छता अभियान की तो निस्संदेह इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो आगाज किया है, जन–जागरण का। हमारी सरकार भी उसके लिए पूरी तरह से चिंतित है। किस तरह से हम लोग सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। हमने पूरे प्रदेश को क्षेत्रीय भेद–भाव से दूर करते हुए, 15 क्लस्टर में डिवाइड किया है। इन 15 कलस्टर के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। कुछ जगह पर वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगाए जाएंगे और कुछ जगह पर वेस्ट टू कम्पोज के प्लांट लगाए जायेंगे। हमारा यह जो प्रॉसिजर है वह शुरू हो चुका है। जहां तक भिवानी का कंसर्न है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि भिवानी के लिए भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे भिवानी कलस्टर का हिस्सा है। हांसी रोड बवानी खेड़ा में 16 एकड़ भूमि पर हम यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं और यह पूरे नॉर्म्स को भी पूरा करता है, क्योंकि जहां पर शहर की आबादी है, यह जगह उससे 2 किलोमीटर दूर है। कचरे से खाद बनाने के लिए 4 कलस्टर भिवानी, भूना, पुन्हाना और हिसार जिसमें नगर परिषद भिवानी भी शामिल है, चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए बोली प्रक्रिया जून, 2017 तक पूर्ण होने की संभावना है और इस कलस्टर के निर्माण के बाद निश्चित रूप से कूड़े की लिफ्टिंग, डम्पिंग, सेग्रीगेशन को कम किया जा सकता है और उसको प्रयोग में

लाया जा सकता है। हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से चिंतित है और हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अब सवाल मत पूछिए। आपको बहुत अच्छा जवाब मिल गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने कहा है कि ये इसके लिए पूरी तरह से चिंतित हैं और जून, 2017 तक इस पर काम शुरू करवा देंगी । क्या ये जून, 2017 तक इस पर कार्य शुरू करवा देंगी ?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने on the floor of the House आश्वासन दिया है । हम जून, 2017 तक इस पर अवश्य काम शुरू करवा देंगे ।

To Enhance Subsidy on Drip Irrigation

***1789.Sh. Om Parkash Barwa.:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that the underground water level is depleting in the State; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance subsidy for the farmers to promote the drip irrigation system to save the water ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड) :हां, श्रीमान् जी, सरकार द्वारा किसानों को टपका सिंचाई प्रणाली समेत सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 50 से 90 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश बरवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि 50 से 90 प्रतिशत तक सबसिडी माईक्रो इरीगेशन पर दी जाती है । क्या मंत्री जी इसकी डिटेल बताने की कृपा करेंगे कि 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सबसिडी को किस तरह से कैटेगराईज किया गया है और 90 प्रतिशत सबसिडी किसको दी जाती है ? क्या सभी किसानों को 90 प्रतिशत सबसिडी देने बारे सरकार विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसमें एस.सीज. कैटेगरी को 90 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। इसी तरह से जो इलाके डैजर्ट डवैल्पमैंट प्रोग्राम के तहत आते हैं वहां पर सीमांत और छोटे किसानों को 75 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है। इसी तरह से

सुखा प्रभावित एरियाज में 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है । इस तरह से सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत तक और छोटे किसानों को 75 प्रतिशत तक सबसिडी दी जाती है । इसके अतिरिक्त एस.सीज. कैटेगरी के किसानों को 90 प्रतिशत तक सबसिडी दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, अभी का जो पैटर्न है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है लेकिन माननीय सदस्य जिस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं, उस बात के महत्व को मैं समझता हूं । क्योंकि अभी हमारी कुल भूमि की 19 प्रतिशत भूमि पर माईक्रो इरीगेशन होती है । आगे का रास्ता माईक्रो इरीगेशन का ही है । हम अपनी सारी की सारी भूमि पर पानी माईक्रो इरीगेशन के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं और भविष्य के लिए भी माईक्रो इरीगेशन से ही पानी उपलब्ध हो सकता है । आज के दिन पूरे प्रदेश में 2 करोड़ एकड़ फीट पानी की उपलब्धता है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त आने वाले दस साल में हमें 1 करोड़ एकड़ फीट पानी अतिरिक्त चाहिए लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं बढ़ा सकते । इस तरह से जो हमारा पानी का 2 करोड़ एकड़ फीट बजट है उसमें 40 लाख एकड़ फीट पानी का सालाना घाटा हो रहा है । माननीय सदस्य ने अपने पहले सवाल में पूछा है कि क्या हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है, उसके जवाब में मैंने बताया है कि हां हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है । ग्राउंट वाटर की औसत गिरावट 9 मीटर है और कुछ एरियाज में तो यह गिरावट 21 मीटर से भी ज्यादा है। इसलिए माईक्रो इरीगेशन ही सिंचाई के लिए बेहतर विकल्प है । हम किसानों को इसकी तरफ ले जाने के लिए अधिक से अधिक कोशिश करेंगे हम कई सारी चीजों को इससे जोड़ रहे हैं, जिस तरह का माननीय सदस्य का सुझाव है ।

श्री ओम प्रकाश बरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जल स्तर की गिरावट पूरे दक्षिणी हरियाणा की समस्या है । यह समस्या अकेले लोहारू हल्के की नहीं है । हल्का लोहारू में अंडर ग्राउंड वाटर जहां पहले 100 फीट पर था, वह अब 400 फीट पर पहुंच गया है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि माईक्रो इरीगेशन के लिए सभी को 90 प्रतिशत सबसिडी दी जाये । इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि होर्टीकल्चर की सबसिडी में किसानों का कोई इंट्रस्ट नहीं है इसलिए वह सबसिडी भी इसमें शामिल की जाये ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है इसलिए इसमें उत्तर देने वाली कोई बात नहीं है ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, कृषि हमारा मुख्य धंधा है । इस पर मुझे भी सप्लीमैंटरी पूछने दी जाये ।

श्री अध्यक्ष : संधु जी, मंत्री जी ने काफी लम्बा जवाब दिया है और इस प्रश्न से संबंधित सारी बातें क्लीयर कर दी हैं ।

Construction of Bye Pass

***1685. Sh. Jagbir Singh Malik .** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state:-

(a) whether it is fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to Construct Bye Pass of Gohana on western side; and

(b) if so, the time by which is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान् जी,

(ख) वर्तमान में समय सीमा नहीं दी जा सकती।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस काम के लिए सी.एम. अनाउंसमैंट को डेढ़ साल से ज्यादा समय हो गया है। जो 3500 अनाउंसमैंट्स हुई है उनमें से एक यह गोहाना की भी है। क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में यह बतायेंगे कि इन्होंने इस कार्य के लिए कितना एरिया चिन्हित किया है, वह किस–किस गांव का एरिया है और वह कुल कितना रकबा बनता है? क्या इस मामले में सैक्शन 4 इत्यादि की कार्यवाही चल रही है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य अब किस स्टेज पर है ? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि कब तक यह काम शुरू होकर कम्पलीट हो जायेगा ?

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भाई जगबीर सिंह जी ने जो यह कहा कि इस अनाउंसमैंट को डेढ़ साल हो गया है मैं उनको यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस अनाउंसमैंट को डेढ़ साल न होकर केवल 13 महीने ही हुए हैं। मैं इस बारे में यह बताना चाहूंगा कि गोहाना के पूर्व में नेशनल हाईवे नम्बर 71 पर एक बाई–पास बनाने पहले ही बना हुआ है। अब ये पश्चिम में भी एक बाई–पास बनाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रोजैक्ट पर कुल मिलाकर लगभग 376 करोड़ रूपये की लागत आने की सम्भावना है। इस

कार्य हेतु जमीन एक्वॉयर की जा चुकी है। इसके साथ ही इस बाई–पास पर दो आर.ओ.बी. भी इन्वॉल्वड हैं। पश्चिम बाई–पास की टैक्नीकल वॉयबिलिटी व बैनीफिट कॉस्ट रेशो बनाई जायेगी। यदि इस प्रोजैक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उचित आई तो उसके बाद हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं आया कि इस प्रोजैक्ट में कितनी जमीन इंवॉल्वड है। यह मामला किस स्टेज पर है। क्या इस मामले में सैक्शन 4 की कार्यवाही हो गई है ? कुल मिलाकर मैं यही पूछना चाहूंगा कि यह केस कहां पर स्टैण्ड करता है ? किसानों को कितना मुआवजा दिया जायेगा ? मैंने यह भी जानना चाहा था कि इस प्रोजैक्ट के लिए कौन–कौन से गांवों की जमीन ली जायेगी ? पहले जो इस बाई–पास की अलाईनमैंट हुई थी तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह अब भी मान्य होगी या फिर इस दिशा में दोबारा से कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस रोड पर एक बाई–पास पहले ही बना हुआ है। हम दूसरे बाई पास बनाने की भी सर्वे करवा लेंगे। अगर नॉर्म्ज पूरे होंगे तो हम इस बाई–पास को बनाने के बारे में विचार कर लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1680

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Re-Construction of Primary School Building

***1675. Sh. Ved Narang. :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the Primary School building of Vikas Nagar in ward No. 17 of Barwala is in dilapidated condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re-construct the above said Primary School building togetherwith the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्री मान जी, विद्यालय का जीर्ण–शीर्ण भवन गिरा दिया गया है और 122.85 लाख रूपये की लागत से विद्यालय के नये भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है जिसका निर्माण मई, 2017 में

आरम्भ होने की संभावना है। स्पीकर सर, वार्ड नम्बर 17, बरवाला में विद्यालय है। वेद नारंग जी का यह कहना सही है कि इस विद्यालय का जो भवन था वह जीर्ण–शीर्ण अवस्था में था। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस भवन को गिरा दिया गया है। इस विद्यालय के नये भवन के 10 कमरों और जो एक प्राथमिक विद्यालय के लिए जरूरी होता है लड़के व लड़कियों के अलग–अलग शौचालयों के लिए 1 करोड़ 22 लाख 85 हजार रूपये की राशि की एक योजना फाईनैंस डिपार्टमैंट द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। अप्रैल, 2017 में वहां पर काम शुरू होने वाला है।

श्री वेद नारंग : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा । इसके साथ ही मैं इनके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि बरवाला हल्के के राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, धांसू में भी ऐसी ही समस्या है। जहां पहली कक्षा से लेकर पांचवी तक लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं, इसी प्रकार से पांचवीं से लेकर 12वीं तक 400 बच्चे पढ़ते हैं। इस प्रकार से इस स्कूल में बच्चों की कुल संख्या में बच्चों 550 है। इस स्कूल के भवन को भी आज से पांच साल पहले जर्जर घोषित किया जा चुका है। तीन साल पहले इस स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी गई थी। वर्तमान समय में 550 बच्चों की संख्या का यह स्कूल केवल मात्र पांच कमरों में चल रहा है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो और चाहे बरसात हो हर मौसम में बच्चों को बाहर खुले आसमान के नीचे ही बैठकर पढ़ना पड़ता है। न ही वहां पर कोई शौचालय है और न ही वहां पर कोई पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि इस स्कूल के मामले पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए इस स्कूल की बिल्डिंग भी जल्दी से जल्दी बनवाई जाये ताकि वहां के बच्चों को हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सके।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विधायक साथी से निवेदन करूंगा कि वे अपने ही लैटर–पैड पर इस विद्यालय का भी लिख कर दे दें । हम उस पर भी कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे।

श्री वेद नारंग : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि पिछले समय विधायक साथी श्री अनूप जी ने भी यह प्रश्न उठाया था कि एक बच्ची की आंखें ऑयरन की गोलियां खाने से खराब हो गई थी। मैं माननीय मंत्री

जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कृपया यह बतायें कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, अनूप जी ने और वेद नारंग जी ने सरोज नाम की लड़की के बारे में लिख कर दिया था। मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। यह जानकारी मैंने इससे पहले भी यहां पर उपलब्ध करवाई थी।

Sanctioned Posts of Lecturers

***1983.Sh. Makhan Lal Singla :** Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that only fifteen posts of Lecturers have been sanctioned for the Government Women College, Sirsa; and

(b) if so, the time by which the more posts of Lecturers are likely to be sanctioned for the said college ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) चूँकि यह महाविद्यालय 2015–16 में ही शुरू हुआ था, इसलिए अधिक पद स्वीकृत करने की मांग का आंकलन आगामी शैक्षणिक सत्र में किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मक्खन लाल सिंगला जी ने पूछा है कि राजकीय महाविद्यालय, सिरसा में प्राध्यापकों के केवल 15 पद स्वीकृत हैं इनको कब तक बढ़ा दिया जायेगा । इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि छात्रों की संख्या के हिसाब से पद स्वीकृत किये जाते हैं । वर्ष 2015–2016 में वहां पर छात्रों की संख्या 1653 थी और वर्तमान में यह संख्या बढ़ गई है । छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुये हमने वहां पर मांगे गये प्राध्यापकों के 12 अतिरिक्त पद स्वीकृत कर दिये हैं और नये सत्र से ये पद मिल जायेंगे ।

श्री मक्खन लाल सिंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं ।

To Set Up Solar Energy Plant in Rania

***1718. Shri Ram Chand Kamboj. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Solar Energy Plant in Rania Assembly Constituency; if so, the time by which the abovesaid plant is likely to be set up ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

मुख्यमंत्री घोषणा दिनांक 24.12.2016 के बाद, डी.सी., सिरसा को रानियां चुनाव क्षेत्र के गांव भरोलियांवाली, नानुआना, मट्टुवाला, दरियावाला और पन्नीवाला मोटा में सौर ऊर्जा स्यंत्रों को स्थापित करने के लिए उपलब्ध पंचायती जमीनों की जानकारी देने का अनुरोध किया है। उसके बाद कंस्लटेंट के जरिये जमीन का साईट सर्वेक्षण/प्रीफिसिबिलटी करवाया जायेगा और प्रीफिसिबिलटी अध्ध्यन के आधार पर सौर स्यंत्रों को लगाने का निर्णय लिया जायेगा। परन्तु, जब तक पंचायती जमीन वास्तव में नहीं मिल जाती तब तक पक्की समयसीमा नहीं दी जा सकती।

श्री राम चंद कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो जवाब सदन के पटल पर रखा गया है कि भरोलियांवाली, नानुआना, मट्टुवाला, दरियावाला और पन्नीवाला मोटा गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जायेंगे । मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या पंचायतों की तरफ से रैजोल्यूशन आये हैं या निजी व्यक्तियों की तरफ से रैजोल्यूशन सरकार के पास आये हैं ? इसके अतिरिक्त मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो ये सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाये जायेंगे वे सब–डिविजन या बिजली घरों के नजदीक लगाये जायें तो अच्छा रहेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24.12.2016 को सिरसा जिले के रानियां विधान सभा क्षेत्र के गांव भरोलियांवाली, नानुआना, मट्टुवाला, दरियावाला और पन्नीवाला मोटा गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा की गई थी । इसके लिए दिनांक 11.1.2017 और दिनांक 2.2.2017 को जमीन विवरण आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए मामला

उपायुक्त, सिरसा के कार्यालय में भेजा गया है ताकि परियोजना के साईट सर्वेक्षण/प्रीफिजिबिलिटी की जा सके । जमीन का अभी तक इंतजार है । जमीन की उपलब्धता के बाद यह कार्य कर दिया जायेगा । इस समय ये जो 2, 3 और 4 गांव हैं अगर उनमें हमें पंचायत की तरफ से जमीन मिल जाती है तो उसको लीज पर लेकर वहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिये जायेंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो यह योजना आई इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ लोग निजी तौर पर भी 1–1 या 2–2 किलोवॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं । क्या मंत्री जी के पास भी इस तरह के कोई प्रस्ताव आये हैं या नहीं, यदि आये हैं तो किस जगह से आये हैं? मैं स्वयं भी इस तरह का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहता हूं क्योंकि आजकल बिजली के बिना कोई भी काम नहीं होता है । मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन गांवों में ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हैं वहां से आवेदन पंचायत की तरफ से प्राप्त हुये हैं या निजी व्यक्तियों की तरफ से प्राप्त हुये हैं या सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव पंचायतों को रैफर किये गये हैं कि ये पंचायतें सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकती हैं? इसके लिए क्या सिस्टम है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, अभी तक एच.पी.जी.सी.एल. ने अलग–अलग 133.20 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाने का लक्ष्य रखा है । इसी प्रकार से वर्ष 2017–18 तक एन.टी.पी.सी. द्वारा 353 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाने का लक्ष्य है और एस.ई.सी.टी. (सोलर ऐनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा वर्ष 2018–19 तक 250 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाने का लक्ष्य है । इसी तरह से एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाने का लक्ष्य है तथा हरेडा द्वारा वर्ष 2021–22 तक 1600 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाने का लक्ष्य है । जैसा कि हमारे साथी ने कहा है कि जहां जमीन की वेस्टेज है क्या वहां पर सौर ऊर्जा लगाने का लाभ है । स्पीकर सर, जमीन का चयन इस प्रकार से किया जा रहा है कि जहां पर ग्राम पंचायतों की जमीन खाली पड़ी हैं और जो जमीन यूटिलाईज नहीं हो रही हैं वहां पर सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए जाएंगे । अगर किसी इंडीविजुअल का सौर ऊर्जा का प्लांट्स लगाने के लिये प्रस्ताव आएगा तो हम वहां सौर ऊर्जा का प्लांट्स लगाने के लिये बढ़ावा देंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानियां में सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है या नहीं है । इन्होंने अपने जवाब में 5–6 गांवों के नाम दिये थे । उन पांच–छः गांवों के नामों के बारे में मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि उन गांवों में सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाने के लिये गांवों की तरफ से प्रस्ताव आए हैं या सरकार की तरफ से उन गांवों में सौर ऊर्जा का सैंटर लगाने की कोई स्कीम है ? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वह कितने–कितने किलोवाट के हैं, कितने मेगावाट के हैं और किस सिस्टम से लगाये जा रहे हैं ? जिन गांवों का सरकार ने इसके लिये चयन किया है उन गांवों को सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी दी जा रही है, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से केवल ये जानना चाहता हूं ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गये थे वहां पर लोगों की डिमांड के ऊपर इन गांवों के अन्दर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए थे । इसके बाद माननीय उपायुक्त महोदय के पास यह सारा मामला सर्वेक्षण के लिये विचाराधीन है । मेरा माननीय साथी से अनुरोध है कि वे उपायुक्त महोदय से मिलकर के इन गांवों के अन्दर जमीन उपलब्ध कराएं । अगर आप इस कार्य में सरकार का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उन गांवों के अन्दर सौर ऊर्जा के प्लांट लगा दिये जाएंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन ने मंत्री जी का जवाब सुन लिया है । फिर भी अगर मंत्री जी मुझसे यह चाहते हैं कि मैं इस कार्य में उनकी मदद करूं तो मैं मदद के लिये तैयार हूं । इसलिये ही मैंने यह प्रश्न पुट किया था जिसमें मैं यही पूछना चाह रहा था कि सरकार की क्या स्कीम है । अगर यह सौर ऊर्जा का प्लांट सब डिवीजनल लेवल पर और बिजली घरों के पास लगाए जाते हैं तो उससे बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा जिससे पूरे प्रदेश को फायदा होगा । मंत्री जी मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि सरकार की तरफ से इन प्लांट्स को लगाने पर क्या सब्सिडी दी जा रही है ? अगर इस तरह से सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाते हैं एक मेगावाट के, दो मेगावाट के तो उस पर सब्सिडी देने का क्या प्रावधान है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये एक नीति बनाई है जिसमें सब्सिडी का प्रोविजन किया गया है । माननीय साथी ने जो कहा है कि अगर यह सौर ऊर्जा का प्लांट सब डिवीजनल लेवल पर

और बिजली घरों के पास लगाए जाते हैं तो उससे बिजली के उत्पादन में लाभ होगा । मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह प्लांट सब डिवीजनल लेवल पर और बिजली घरों के पास लगाने से लाभ वाली बात नहीं है क्योंकि सौर ऊर्जा जो उपलब्ध होगी और हमारा जो इसका कन्ट्रोल है जैसे 132 के.वी.ए. है । 220 के.वी.ए. है यह उनको सप्लाई देगा । इसमें प्लांट के साथ लगाने वाली तो कोई बात नहीं है । जो जमीन वेस्टेज है वहां पर यह प्लांट्स स्थापित किये जाएंगे । इन प्लांट्स को बिजली घरों के साथ अटैच करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सौर ऊर्जा की सप्लाई किसी बिजली प्लांट के साथ अटैच नहीं है । जहां तक सब्सिडी की बात है, सब्सिडी का सरकार की तरफ से प्रोविजन है ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर इस प्लांट को किसान लगाता है तो उसको कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह हिदायत है कि अगर कोई इंडीविजुअल व्यक्ति सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना चाहता है या कोई किसान लगाना चाहता है तो हम उनको सब्सिडी देंगे । अब तक हमने जो सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध करवायी है वह 82 मेगावाट बिजली उपलब्ध हुई है । जिसको हमने रूफ लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर स्थापित करके चालू किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया ही नहीं कि इसमें किसान को कितनी सब्सिडी मिलेगी ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी की प्रोपर रूप से जानकारी मैं माननीय विधायक के पास भिजवा दूंगा कि इसमें किसान को कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिये जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट साईन हुआ है वह किस रेट पर साईन हुआ है ? पहले तो यह 11 रूपये, 12 रूपये और 17 रूपये था क्योंकि ये जब शुरूआत से चले थे उस समय यह कॉन्ट्रैक्ट 17 रूपये कुछ पैसे से चले थे । सौर ऊर्जा का जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वह किस रेट पर हुआ था ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पानीपत थर्मल प्लांट में 10 मेगावाट का प्लांट लगा है उसका पर मेगावाट साढे छः करोड़ रूपये खर्चा आया है । एक मेगावाट का साढ़े छः करोड़ रूपये खर्च है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, ये तो रेट पूछ रहे हैं कि किसान जो बिजली सरकार को देगा उसको सरकार किस रेट में लेगी ?

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से पर यूनिट का रेट पूछ रहा हूं । जो आपका एग्रीमैंट हुआ है । उसके हिसाब से आप किसान से यह बिजली किस रेट पर लेंगे ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये 4.88 रूपये पर यूनिट का रेट तय हुआ है ।

To Reclaim the Agriculture Land

***1689. Sh. Parminder Singh Dhull. :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to test the quality of soil and to reclaim the agricultural land in the State; if so, the time by which it is likely to be materialized ?

2:00 बजे

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : एक केन्द्रीय चालित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रदेश मे वर्ष 2015–16 से लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत सभी किसानों को 31 मार्च, 2017 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। लवणीय/ सेम तथा क्षारीय समस्याओं से ग्रस्त कृषि भूमि का सुधार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राज्य प्लान योजना के अन्तर्गत वार्षिक परियोजनाओं के आधार पर किया जा रहा है। ऐसी कृषि भूमि का उपचार एक लगातार प्रक्रिया है । इस संबंध में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वर्ष 2015–16 से प्रदेश में एक सैंट्रली स्पॉंसर्ड सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 31 मार्च, 2017 तक सॉयल हैल्थ कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, लगभग सारे हरियाणा के सॉयल सैंपल ले लिए गए हैं और 9 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड हम अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वैसे तो सभी किसानों को 31 मार्च, 2017 तक सॉयल हैल्थ कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन विभाग से रिपोर्ट लेने के पश्चात मैं अब इसमें थोड़ा सी

करेक्शन करता हूँ और वह यह है कि बाकी बचे 3 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड हमें और बांटने हैं जिसके लिए कम से कम तीन महीने और लगेंगे और इस समयावधि में हम हर खेत का सॉयल हैल्थ कार्ड किसान के पास पहुंचा देंगे। इसके अतिरिक्त यह बताना भी उचित समझता हूँ कि लवणीय/सेम तथा क्षारिय कृषि भूमि के सुधार के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, वह सतत प्रक्रिया का एक रूप है जो सतत चलती रहती हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने योजनाओं का तो जिक्र कर दिया है लेकिन यह नहीं बताया है कि जो जमीन लगातार सेम से प्रभावित हैं और इस समस्या की वजह से जहां पर कई सालों से खेती नहीं हुई है, उन खेतों के किसानों को सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जायेगी? जैसाकि आपने बताया कि लवणीय/सेम तथा क्षारिय कृषि भूमि के सुधार के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, वह सतत प्रक्रिया का एक रूप है जो सतत चलती रहती हैं। इसके कोई शक नहीं है कि यह योजनाएं चलती रहती हैं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि पिछले 10 वर्षों से मेरे हल्के में तथा हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों में सेम व लवणीय वजह से खराब हो चुकी हजारों एकड़ जमीन जिसमें किसान फसल नहीं बो पा रहे हैं, उन पीड़ित किसानों को क्या सरकार सहायता देने संबंधी कोई योजना बना रही है ताकि किसान ठीक से जीवन यापन कर सकें ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। बहुत सारी जमीने ऐसी हैं जो वाटर लागिंग व लवणता के कारण दोनों फसलें नहीं दे पा रही हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने इस तरह का प्रश्न करके एक तरह से सरकार को सुझाव दिया है कि जिन किसानों की जमीन में लगातार जल भराव है या लवणता है और जिसकी वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे है; उन किसानों को सरकार की तरफ से किसी न किसी प्रकार का सहयोग जरूर करना चाहिए तो इस परिपेक्ष्य में मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि उनके द्वारा उठाये गए इस सवाल पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

श्रीमती प्रेम लताः अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में मैं भी माननीय मंत्री महोदय से एक सप्लीमैंटरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के के बधाना गांव में हॉर्टिकल्चर सैंटर खोलने की घोषणा की थी लेकिन दुख

इस बात का हुआ कि विभागीय अधिकारियों द्वारा डी.सी. को रिपोर्ट भेजी गई कि यहां की जमीन खराब है। चूंकि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान विकास योजना लवणीय/सेम तथा क्षारिय भूमि का सुधार करने वाली एक सैट्रर्ली स्पॉसर्ड स्कीम है, तो इस परिपेक्ष्य में मेरा अनुरोध है कि पोजिटिव रूख के साथ सैंट्रर्ली स्पॉसर्ड स्कीम के माध्यम से गांव बधाना की जमीन में जो खराबी है, को ठीक करवाया जाये ताकि यहां पर हॉर्टिकल्चर सैंटर खोला जा सके?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, यदि ध्यान से देखा जाये तो यह दोनों इश्यूज बिल्कुल सैपरेट हैं। जहां पर बागवानी विश्वविद्यालय का कोई रीजनल सैटर खोला जाता है, वहां की जमीन और पानी दोनों अव्वल किस्म के होने बहुत जरूरी हैं क्योंकि यहां पर जो प्रयोग किए जाते हैं, बाद में इन्हीं प्रयोगों के आधार जो निष्कर्ष निकलते हैं वह निष्कर्ष हरियाणा व देश के दूसरे प्रदेशों के किसानों के खेतों में फलीभूत होते हैं इसलिए यह तो क्लीयर हो गया कि जो बैस्ट जगह होगी केवल उसी जगह हॉर्टिकल्चर सैंटर बनाया जायेगा। दूसरा विषय यह है कि मान लो कहीं पर जमीन खराब है और उसमें सुधार करके उस जमीन को एक, दो या पांच प्रकार की खेती के योग्य बनाया जाये, यह अलग विषय है। अतः जहां तक गांव बधाना के खेतों को ठीक करके खेती योग्य बनाने की बात है तो सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रयोग करते हुए बधाना के खेतों की कमियों को दूर करने का काम किया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Irregularities in Desilting of Ghaggar River in Sirsa

***1698 Shri Karan Singh Dalal & Shri Abhay Singh Chautala. :**Will the Chief Minister be pleased to state.

(a) whether any irregularity/mis-appropriation of funds in the work of embankment/desilting of Ghaggar River in District Sirsa during the year 2015 to till to date has come to the notice of the Government; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the action taken in the matter?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हॉ, श्रीमान जी।

(ख) 7 जनवरी, 2017 को 'द ट्रिब्यून' में अनियमितताओं के बारे में छापी गई खबर की जांच जारी है तथा रिपोर्ट आनी अभी बाकी है ।

To Start the Bus Service for the Girl Students

***1759 Shri. Anoop Dhanak. :** Will the Transnport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start the bus service for the girl students from Uklana Mandi to Hisar; if so, the time by which the said bus service is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, यह बस सेवा पहले से ही चलाई जा रही है।

Problem of Water logging

***1775 Sh. Tek Chand Sharma. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the problem of waterlogging in Harfala, Mohla, Bhankpur, Kabulpur, Ladhiapur, Sikaranna, Firozpur Kalan, Jahkhopur, Bijopur, Karnera villages in Prithla Assembly Constituency; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

कृषि मन्त्री : श्रीमान्, सूचना सदन के पटल पर रखी है ।

सूचना

1. किसानों तथा श्री टेक चन्द शर्मा, माननीय् एम0एल0ए0 पृथला के आग्रह पर केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सी0एस0एस0आर0आई0), करनाल के

वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों तथा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक 6–5–2015 को प्रभावित गांवों का दौरा किया गया ।

2. टीम द्वारा प्रस्तुत की गई सम्भाव्यता रिर्पोट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में लगभग एक मीटर की गहराई पर 10–30 सै0मी0 मोटी कठोर कंकर की परत है । कठोर कंकर की परत का होना न केवल मशीनों द्वारा सतह निकासी पाईप प्रभावी तौर से बिछाने में बाधा उत्पन्न करेगा बल्कि इन पाईपों के बिछाये जाने के बावजूद भी लवणों के पर्याप्त निक्षालण को भी बाधित करेगा । प्रभावित क्षेत्र में नहरी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नही है जो इस प्रणाली में लवणों के निक्षालण के लिए आवश्यक है।

3. टीम द्वारा की गई सिफारिश :–

- इन प्रभावित गांवो में जल भराव तथा मृदा लवणता के नियन्त्रण के लिये छिछले नलकूपों जैसे अन्य विकल्पों को तलाशा जाये ।
- बेहतर जल स्तर नियन्त्रण के लिये क्षेत्र में से गुजरने वाले मुख्य गोच्छी नाले को गहरा तथा साफ करना ।

4. छिछले नलकूपों को लगाने का कार्य सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के साथ विचार–विमर्श उपरान्त किया जायेगा ।

5. मुख्य गोच्छी नाले की गाद निकालने तथा सफाई का कार्य सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग द्वारा मौके की आवश्यकता अनुसार किया जायेगा ।

6. विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त प्रभावित गांवो में से गुजरने वाले मुख्य गोच्छी नाले को गहरा करने बारे भी सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग द्वारा विचार किया जायेगा ।

Reconstruction of PWD B&R Rest House

***1769 Sh. Udai Bhan. :** Will the PW(B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the P.W.D B&R Rest House in Hodal has been declared unsafe due to its dilapidated condition; if so , the steps taken by the Government to reconstruct the said Rest House?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान जी। कच्चा अनुमान की प्रकिया प्रगति पर है।

Desilting of Dirty Nullah

***1735. Shri Lalit Nagar. :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the dirty Nullah from Durga Builder Gate to Tilpat Yamuna in Tigaon Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी । दुर्गा बिल्डर गेट से तिलपट्ट यमुना तक गन्दे नाले (सेहतपुर ड्रेन) की मुरम्मत करने की एक योजना बनाई गई है । यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा कोड नं. 12415 दिनांक 17.04.2016 के अन्तर्गत आता है । इस गन्दे नाले (सेहतपुर ड्रेन) की लम्बाई 19000 फुट है । ड्रेन की आर0डी0 0 से 19000 तक गाद निकालने का कार्य किया जाएगा । ड्रेन की आर0डी0 11000 से 19000 तक लाईनिंग का कार्य भी किया जाना है । 7.95 करोड़ रू0 की लागत के इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मामला विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न एंव उत्तर

Appellate Authority for Haryana State Pollution Control Board

416 Shri Karan Singh Dalal. : Will the Environment Ministry be pleased to state:

(a) Whether there is any proposal under consideration of the government to constitute Appellate Authority for Haryana State Pollution Control Board?

(b) If so, the time by which it is likely to be constituted?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) :

(क) हॉ श्रीमान, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लिए अपीलीय प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) शीध्र ही, इसके गठन की सम्भावना है ।

Total Premium Collected by the Insurances Companies

422. Sh. Parminder Singh Dhull. : Will the Agriculture Minister be pleased to state theseason-wise, constituency-wise and crop-wise details of the total premium collected by the insurance companies operating under PardhanMantriFasalBima Scheme in the State?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान्जी, निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरे विभाग द्वारा तैयार नहीं किए जाते। प्रधान मन्त्री फसल बीमा योजना के अधीन चल रही बीमा कम्पनियों द्वारा सीजनवार, फसलवार तथा जिलावार कुल एकत्रित किए गए प्रिमियम का ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

ब्यौरा

राज्य में प्रधान मन्त्री फसल बीमा योजना के अधीन चल रही बीमा कम्पनियों द्वारा सीजनवार, जिलावार तथा फसलवार कुल एकत्रित किए गए प्रिमियम का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0	जिले का नाम	खरीफ 2016				रबी2016-17(संभावित)			
		कपास	धान	बाजरा	मक्का	गेहू	जौं	सरसों	चना
1	सिरसा	1528.29	317.54	4.30	1.02	1009.97	1.44	19.19	2.94
2	भिवानी	3320.97	333.83	347.83	0.94	712.02	1.75	230.13	71.63
3	फरीदाबाद	0.68	69.23	2.54	0.02	69.57	0	0.02	0
4	कुरुक्षेत्र	3.95	568.77	0	0	353.54	0	0.41	0.22
5	कैथल	27.34	690.55	0.85	0.17	481.51	0	0.12	0.06
6	पचंकुला	1.70	112.79	0.11	1.97	94.20	0.06	0.36	0.50
7	रेवाड़ी	109.23	30.77	409.94	0.01	302.99	0.27	101.90	0.02
8	हिसार	4234.32	716.36	33.28	0.17	1059.03	0	605.16	0
9	सोनीपत	6.71	1174.05	14.01	0.04	673.64	0	0	0
10	गुरुग्राम	5.21	58.43	45.25	0.04	113.29	0	97.10	0
11	करनाल	3.99	1581.57	1.30	0.08	840.70	0	0	0
12	अम्बाला	1.71	823.49	0.01	0.01	508.69	0	0	0
13	जीन्द	991.21	1413.76	8.15	0.18	916.68	0	0	0
14	महेन्द्रगढ	209.95	3.87	452.48	0.02	439.61	0	74.11	39.80
15	फतेहाबाद	269.24	394.18	2.46	0.00	540.00	24.00	48.00	16.45
16	रोहतक	760.09	1399.28	262.53	20	161.26	2.49	16.33	3.01
17	झज्जर	124.73	580.73	35.08	0	135.00	0.09	3.33	0
18	मेवात	4.85	38.96	25.17	0.004	86.67	1.87	12.67	0
19	पलवल	23.11	343.69	5.03	0.06	244.84	0.17	0.42	0.05
20	पानीपत	0	636.24	0.01	0	266.38	0	0	0
21	यमुनानगर	0	551.80	0.05	0.06	270.00	0.04	0.10	0.06
	कुलजोड़	**11627.29**	**11839.88**	**1650.38**	**24.82**	**9279.59**	**32.18**	**1209.35**	**134.74**

To Approve the Bus Stop

450. Shri Rajdeep Phogat. : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to approve Bus Stop in the village Sonph-Kasani and Lamba-Kohlawas; if so, the time by which the buses are likely to be halted in these villages ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी, इन गांवों में पहले से ही बसों का ठहराव निश्चित हैं।

Installation of New Sub-Stations

461. Shri Zakir Hussain.: Will the Chief Minister be pleased to state the district wise, Head Wise and year wise details of the amount spent by the department in the last 12 years on all departmental works i.e. installation of New Sub-stations and replacement of conductors?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्ष 2005–06										
क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	--	--	1	182.42	279.26	121.61	304.03
2	सोनीपत	--	--	--	--	1	210.31	89.59	56.76	267.07
3	झज्जर	--	--	--	--	1	183.85		0	183.85
4	पानीपत	--	--	--	--	2	430.37	181.6	88.14	518.51
5	करनाल	--	--	--	--	3	537.27	42.5	7.65	544.92
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	--	--	0	33.08	8.91	8.91
7	कैथल	--	--	--	--	--	0		0	0
8	अम्बाला	--	--	--	--	--	0	10.87	3.006	3.006
9	यमुनानगर	--	--	--	1	--	267.87	112.47	42.68	310.55
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	7.25	2.004	2.004

11	गुरूग्रम	--	--	--	1	--	300	13.98	69.89	369.89
12	फरीदाबाद	--	--	--	1	--	190	280.62	200.5	390.5
13	जींद	--	--	1	--	--	209	167.7	62.04	271.04
14	हिसार	--	--	--	--	1	197	60.34	28.95	225.95
15	भिवानी	--	--	--	--	1	177	81	16.85	193.85
16	सिरसा	--	--	--	--	2	388	43.1	11.28	399.28
17	पलवल	--	--	--	--	--	0	89.82	73.68	73.68
18	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	--	0	84	15.12	15.12
19	रेवाड़ी	--	--	--	--	--	0	52.4	9.43	9.43
20	फतेहाबाद	--	--	--	--	--	0	409.45	205.36	205.36
वर्ष 2006–07										
क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	--	--	1	211.27	42.7	12.28	223.55
2	सोनीपत	--	--	--	--	1	233.04	443.71	140.74	373.78
3	झज्जर	--	1	--	--	--	4600	113	38.09	4638.09
4	पानीपत	--	--	--	--	--	0	148.32	79.53	79.53
5	करनाल	--	--	--	--	3	614.35	61.4	12.5	626.85
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	--	--	0	33.41	9.02	9.02
7	कैथल	--	---	--	--	--	0	0	0	0
8	अम्बाला	--	--	--	1	--	320	19.28	5.59	325.59
9	यमुनानगर	--	--	--	--	--	0	93.48	35.48	35.48
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	12.85	3.724	3.724
11	मेवात	--	--	--	1	--	480	0	0	480
12	फरीदाबाद	--	--	--	1	0	215	300.89	222.05	437.05
13	पलवल	--	--	--	1	--	490	91.02	74.92	564.92
14	फतेहाबाद	--	--	1	--	1	864	299.4	156.08	1020.08
15	भिवानी	--	--	--	--	3	580	86.58	19.14	599.14
16	गुरूग्रम	--	--	--	--	--	0	21.37	106.87	106.87
17	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	1	186	30	5.4	191.4
18	रेवाड़ी	--	--	--	--	--	0	59.2	10.66	10.66
19	हिसार	--	--	--	--	--	0	22.18	21.17	21.17
20	सिरसा	--	--	--	--	--	0	68.05	24.51	24.51
21	जीन्द	--	--	--	--	--	0	102.4	38.91	38.91
वर्ष 2007–08										
क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
1	रोहतक	--	--	--	--	4	1023.86	63.2	21.33	1045.19
2	सोनीपत	--	--	--	--	--	0	247.22	183.9	183.9
3	झज्जर	--	--	1	--	--	786	97.8	33.41	819.41
4	पानीपत	--	--	--	--	--	0	59.7	55.45	55.45
5	करनाल	--	1	--	--	2	3201.01	72	14.4	3215.41

6	कुरूक्षेत्र	--	1	--	1	1	3354.44	31.9	8.62	3363.06
7	कैथल	--	--	--	--	9	2019.2		0	2019.2
8	अम्बाला	--	--	--	1	--	320	46.07	13.15	333.15
9	यमुनानगर	--	--	--	--	1	231.03	109.35	41.5	272.53
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	30.71	8.76	8.76
11	गुरूग्रम		1		2	--	2972	28.9	144.8	3116.8
12	फतेहाबाद	--	--	1	--	--	370	372.7	191.95	561.95
13	हिसार	--	--	1	--	1	909	112.22	66.52	975.52
14	जीन्द	--	--	2	--	--	986	67.6	26.36	1012.36
15	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	1	215	65	11.7	226.7
16	रेवाड़ी	--	--	--	--	2	412	68.9	13.3	425.3
17	भिवानी	--	--	--	--	5	1078	81	18.95	1096.95
18	सिरसा	--	--	--	--	6	1164	72.38	23.53	1187.53
19	फरीदाबाद	--	--	--	--	--	0	356.75	254.84	254.84
20	पलवल	--	--	--	--	--	0	97.32	82.92	82.92
21	मेवात	--	--	--	--	--	0	12.5	10.65	10.65
वर्ष 2008–09										
क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	2	--	4	2991.63	88.7	31.05	3022.68
2	सोनीपत	--	--	1	--		2300	587.95	262.88	2562.88
3	झज्जर	--	--	1	--	1	1133.73	85.8	30.63	1164.36
4	पानीपत	--	--	--	--	2	645.78	35.9	50.49	696.27
5	करनाल	--	--	1	--	2	1271.49	54.6	12.3	1283.79
6	कुरूक्षेत्र	--	1	--	2	1	5952.9	36.35	9.8	5962.7
7	कैथल	--	--	1	--	1	1011.53	15.25	3.81	1015.34
8	अम्बाला	--	--	--	--	--	0	33.32	11.83	11.83
9	यमुनानगर	--	--	--	--	--	0	117.15	44.46	44.46
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	22.21	7.89	7.89
11	गुरूग्रम	--	--	--	1	--	500	27.35	246.2	746.2
12	फरीदाबाद	--	--	--	1	--	321	554.04	463.82	784.82
13	फतेहाबाद	--	1	--	--	2	2649	84.1	55.1	2704.1
14	भिवानी	--	1	--	--	7	2736	79	19	2755
15	हिसार	--	--	1	--	2	845	107.57	65.56	910.56
16	जीन्द	--	--	1	--	--	942	111.5	46.83	988.83
17	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	4	827	50.00	10	837
18	सिरसा	--	--	--	--	3	603	52.00	17.22	620.22
19	रेवाड़ी	--	--	--	--	3	609	63.00	13.19	622.19
20	पलवल	--	--	--	--	--	0	131.81	112.7	112.7
21	मेवात	--	--	--	--	--	0	19.6	16.76	16.76
वर्ष 2009–10										

क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	1	--	1	964.72	95.3	33.36	998.08
2	सोनीपत	--	--	--	--	3	723.33	132.45	76.21	799.54
3	झज्जर	--	--	--	--	2	708.72	101.5	33.68	742.4
4	पानीपत	--	--	1	--	--	1400	38.3	48.52	1448.53
5	करनाल	--	--	1	--	1	1007.78	56.5	13.5	1021.28
6	कुरूक्षेत्र	--	--	5	--	7	6580.1	69.53	20.48	6600.58
7	कैथल	--	--	--	--	1	164.06	26.1	5.74	169.8
8	अम्बाला	--	--	--	1	--	690	29.3	11.36	701.36
9	यमुनानगर	--	--	--	1	--	587.18	82.44	31.29	618.47
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	19.53	7.57	7.57
11	गुरूग्रम	--	1	--	3	--	6200	44.22	397.94	6597.94
12	हिसार	1	--	1	--	--	10588	21.24	32.28	10620.28
13	फतेहाबाद	--	--	2	--	4	2277	175	86.13	2363.13
14	भिवानी	--	--	--	--	6	1391	72	18.5	1409.5
15	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	3	725	45	9.9	734.9
16	रेवाड़ी	--	--	--	--	1	206	59.5	13.45	219.45
17	सिरसा	--	--	--	--	5	1165	68.47	41.47	1206.47
18	फरीदाबाद	--	--	--	--	--	0	360.4	225.24	225.24
19	पलवल	--	--	--	--	--	0	117.72	100.65	100.65
20	मेवात	--	--	--	--	--	0	8	6.84	6.84
21	जीन्द	--	--	--	--	--	0	178.3	76.66	76.66

वर्ष 2010–11

क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	--	--	1	345.25	90	31.5	376.75
2	सोनीपत	--	1	1	--	2	6126.63	332.64	128.66	6255.29
3	झज्जर	--	1	--	--	--	4600	95.5	32.5	4632.5
4	पानीपत	--	1	2	--	--	6700	73.5	64.53	6764.53
5	करनाल	--	1	3	--	3	5441.43	83.2	19.3	5460.73
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	1	1	1162.19	55.03	16.19	1178.38
7	कैथल	--	--	--	--	12	4215.8	29.5	7.08	4222.88
8	अम्बाला	--	--	--	1	1	1431.49	21.75	6.62	1438.11
9	यमुनानगर	--	--	--	1	--	243.44	102.12	38.75	282.19
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	14.5	4.42	4.42
11	गुरूग्रम	1	--	--	1	--	8848	30.5	270.37	9118.37
12	जीन्द	--	--	3	--	--	2568	77.8	33.45	2601.45
13	फरीदाबाद	--	--	--	--	--	0	303.77	242.95	242.95
14	फतेहाबाद	--	--	--	--	4	952	100.84	51.44	1003.44
15	सिरसा	--	--	--	--	1	285	70.25	29.41	314.41
16	मेवात	--	--	--	--	1	291	6.5	5.56	296.56

17	भिवानी	--	--	--	--	3	855	78.22	22.64	877.64
18	हिसार	--	--	--	--	1	189	25.3	40.25	229.25
19	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	1	241	35	7.7	248.7
20	रेवाड़ी	--	--	--	--	--	0	60	13.58	13.58
21	पलवल	--	--	--	--	--	0	113.97	97.44	97.44
वर्ष 2011–12										
क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	1	--	3	2103.35	265.99	75.37	2178.72
2	सोनीपत	--	--	--	--	3	986.85	166.53	108.31	1095.16
3	झज्जर	--	--	--	--	2	761.01	121	35	796.01
4	पानीपत	--	1	1	--	--	6000	87	75.34	6075.34
5	करनाल	--	--	4	--	9	5079.73	58	13.92	5093.65
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	--	--	0	72.24	21.21	21.21
7	कैथल	--	--	1	--	3	2017.82	22.15	5.09	2022.91
8	अम्बाला	--	--	--	--	--	0	11.58	4.76	4.76
9	यमुनानगर	--	--	--	1	--	600	98.65	37.44	637.44
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	7.72	3.18	3.18
11	गुरूग्रम	--	2	--	1	--	10903.12	165.88	392.67	11295.79
12	रेवाड़ी	--	--	--	--	1	204	57.68	13.96	217.96
13	सिरसा	1	1	3	--	3	13406	72.49	45.03	13451.03
14	हिसार	--	1	--	--	--	2500	75.43	47.34	2547.34
15	भिवानी	--	--	1	--	2	772	192.49	60.24	832.24
16	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	1	263	55.44	13.2	276.2
17	फरीदाबाद	--	--	--	--	--	0	144.17	130.99	130.99
18	पलवल	--	--	--	--	--	0	117.92	102	102
19	मेवात	--	--	--	--	--	0	5	4.33	4.33
20	फतेहाबाद	--	--	--	--	--	0	145.5	91.31	91.31
21	जीन्द	--	--	--	--	--	0	226.4	99.61	99.61
वर्ष 2012–13										
क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	--	--	--	0	180	51	51
2	सोनीपत	--	--	--	--	1	390.71	56.21	78.97	469.68
3	झज्जर	--	--	1	--	--	965	257.2	158.38	1123.38
4	पानीपत	--	--	--	--	3	1033.32	65.6	75.21	1108.53
5	करनाल	--	1	--	--	--	1123.46	73.3	19.8	1143.26
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	--	--	0	75.78	21.01	21.01

7	कैथल	--	--	--	--	--	0	24.51	35.55	35.55
8	अम्बाला	--	1	--	2	--	4183	23.51	9.4	4192.4
9	यमुनानगर	--	1	--	--	--	3092.44	104	39.47	3131.91
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	15.67	6.27	6.27
11	गुरूग्रम	--	--	--	1	1	459	114.44	411.34	870.34
12	रेवाड़ी	--	1	--	--	2	3801	43.82	14.6	3815.6
13	फरीदाबाद	1	1	--	1	--	14344	320.15	257.74	14601.74
14	भिवानी	--	2	2	--	3	7349	441.66	133.61	7482.61
15	हिसार	--	--	--	--	4	979	401.6	316.15	1295.15
16	सिरसा	--	--	--	--	11	2799	56.69	15.13	2814.13
17	मेवात	--	1	--	--	1	2990	42.5	36.76	3026.76
18	पलवल	--	--	--	--	--	0	147.21	127.34	127.34
19	महेन्द्रगढ़	1	--	2	--	--	9783.39	218.6	54.5	9837.89
20	फतेहाबाद	--	--	--	--	--	0	32.37	25.48	25.48
21	जीन्द	--	--	--	--	--	0	174.37	73.23	73.23

वर्ष 2013–14

क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	1	--	2	2325.14	324	544.91	2870.05
2	सोनीपत	--	--	1	--	3	2241.8	162.91	190.72	2432.52
3	झज्जर	--	1	3	--	1	8209.52	84.6	65.71	8275.23
4	पानीपत	--	--	--	--	4	1156.03	142.2	244.94	1400.97
5	करनाल	--	--	--	--	--	0	86.3	23.3	23.3
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	--	--	0	73.07	37.88	37.88
7	कैथल	--	--	---	--	4	2292.4	142.1	65.05	2357.45
8	अम्बाला	--	--	--	--	--	0	15.68	7.31	7.31
9	यमुनानगर	--	--	--	--	--	0	175.7	66.69	66.69
10	पंचकुला	--	--	--	1	--	1292	52.45	308.99	1600.99
11	गुरूग्रम	--	--	--	1	--	4500	165.2	586.83	5086.83
12	रेवाड़ी	--	--	1	1	2	2019.56	71.85	4.19	2023.75
13	पलवल	--	--	--	1	--	550	110.42	95.51	645.51
14	फतेहाबाद	--	1	--	--	4	3616	43.25	29.2	3645.2
15	भिवानी	--	--	1	--	4	2097	448	284.22	2381.22
16	हिसार	--	--	--	--	3	673	52.5	35.44	708.44
17	सिरसा	--	--	--	--	1	235	66.23	18.52	253.52
18	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	4	860	153.44	43.19	903.19
19	मेवात	--	--	--	--	1	221	46.42	40.15	261.15
20	फरीदाबाद	--	--	--	--	--	0	301.3	180.57	180.57
21	जीन्द	--	--	--	--	--	0	130.18	55.97	55.97

वर्ष 2014–15

क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या	नव निर्मित कार्यरत	बदले गए कंडक्टर	कंडक्टर बदलने पर	कुल योग (ए+बी)

							सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	(किलोमीटर में)	खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	(लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	--	--	1	389.97	233.035	315	704.97
2	सोनीपत	--	--	1	--		1300	192.14	232.68	1532.68
3	झज्जर	--	--	--	--		0	121.52	73.29	73.29
4	पानीपत	--	--	--	--	3	969.86	201.7	369.67	1339.53
5	करनाल	--	--	--	--	3	769.39	68	18.36	787.75
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	--		0	145.94	59.42	59.42
7	कैथल	--	---	--	--	1	260.32	65.1	73.36	333.68
8	अम्बाला	--	--	--	--	--	0	34.8	15.2	15.2
9	यमुनानगर	--	--	--	--	--	0	38.525	14.62	14.62
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	23.2	10.14	10.14
11	पलवल	--	--		1	--	580	622.85	580.25	1160.25
12	फतेहाबाद	--	--	1	--	--	722	72.43	42.96	764.96
13	भिवानी	--	--	1	--	2	1276	231.63	82.33	1358.33
14	फरीदाबाद	--	--	--	--	2	485	176.74	103.22	588.22
15	मेवात	--	--	--	--	--	0	20.5	17.73	17.73
16	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	--	0	66.2	18.7	18.7
17	रेवाड़ी	--	--	--	--	--	0	15.25	3.69	3.69
18	हिसार	--	--	--	--	--	0	22.4	13.29	13.29
19	सिरसा	--	--	--	--	--	0	3	6.35	6.35
20	जीन्द	--	--	--	--	--	0	73.2	18.2	18.2
वर्ष 2015–16										
क्र.सं.	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	--	--	--	0	141.56	191.35	191.35
2	सोनीपत	--	--	3	--	5	5641.29	186	220.82	5862.11
3	झज्जर	--	--	--	--	2	736.06	128.4	49.77	785.83
4	पानीपत	--	--	1	--	7	4492.3	685.5	946.83	5439.13
5	करनाल	--	--	--	--	6	2174.61	67.5	20.92	2195.53
6	कुरूक्षेत्र	--	--	--	--	--	0	78	24.77	24.77
7	कैथल	--	--	--	--	3	1925.9	128.2	741.38	2667.28
8	अम्बाला	--	1	--	4	--	5275.94	21.66	10.83	5286.77
9	यमुनानगर	--	--	--	--	--	0	83.93	31.85	31.85
10	पंचकुला	--	--	--	1	--	965	14.44	7.22	972.22
11	गुरूग्रम	--	--	--	1	--	2500	49.6	965.71	3465.71
12	रेवाड़ी	--	1	--	--	1	4207	27.8	15.96	4222.96
13	फरीदाबाद	--	1	--	--	--	2500	159	68.61	2568.61
14	फतेहाबाद	--	--	1	--	2	1200	84.68	205.38	1405.38
15	हिसार	--	--	--	--	1	255	41.1	25.45	280.45
16	सिरसा	--	--	--	--	1	206	36.75	32.24	238.24
17	भिवानी	--	--	--	--	2	446	68	51.38	497.38

18	जीन्द	--	--	--	--	1	206	111.23	56.8	262.8
19	पलवल	--	--	--	--	--	0	325.12	608.8	608.8
20	मेवात	--	--	--	--	--	0	125	108.13	108.13
21	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	--	0	73.88	35.8	35.8
वर्ष 2016–17(31.01.2017 तकं)										
Ø-la-	जिले का नाम	चालू किए गए नए सब–स्टेशनों की संख्या					नव निर्मित कार्यरत सब–स्टेशनों की लागत (लाख में) (ए)	बदले गए कंडक्टर (किलोमीटर में)	कंडक्टर बदलने पर खर्च धनराशि (लाख में) (बी)	कुल योग (ए+बी) (लाख में)
		400 केवी	220 केवी	132 केवी	66 केवी	33 केवी				
1	रोहतक	--	--	--	--	1	415.93	55.36	74.84	490.77
2	सोनीपत	--	--	--	--	2	576.19	131.03	183.13	759.32
3	झज्जर	--	--	--	--	1	247.84	40.6	17.41	265.25
4	पानीपत	--	--	--	--	1	439.12	571	646.41	1085.53
5	करनाल	--	--	---	---	3	718.57	56.4	18.64	737.21
6	कुरूक्षेत्र	--	---	---	---	--	0	35.1	11.17	11.17
7	कैथल	--	--	--	--	3	1135	9.5	631.32	1766.32
8	अम्बाला	--	--	--	1	--	749	13.98	7.39	756.39
9	यमुनानगर	--	--	--	--	4	1304.8	32.51	12.34	1317.14
10	पंचकुला	--	--	--	--	--	0	9.32	4.92	4.92
11	गुरूग्रम	--	1	--	1	--	7558	89.06	846.68	8404.68
12	फतेहाबाद	--	1	--	--	8	4937	309.4	222.21	5159.21
13	भिवानी	--	--	1	--	1	1174	57.14	19.49	1193.49
14	हिसार	--	--	--	--	2	651	136.71	98.18	749.18
15	सिरसा	--	--	--	--	7	1666	3.58	7.5	1673.5
16	रेवाड़ी	--	--	--	--	1	256	15.3	4.38	260.38
17	महेन्द्रगढ़	--	--	--	--	1	312	53.68	15.18	327.18
18	मेवात	--	--	--	--	2	590	56.5	48.87	638.87
19	फरीदाबाद	--	--	--	--	--	0	136.8	71.34	71.34
20	जीन्द	--	--	--	--	6	1256	28.3	13.3	1269.3
21	पलवल	--	--	--	--	--	0	95.46	82.57	82.57

Paternity Leave and D.D. Entry

***447.Shri Pirthi Singh. :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) Whether the weekly rest and facility of paternity leave is available to the police personnel in the State;

(b) if so, the details of paternity leave applied by the police personnel in the Nuh District during the last 6 months together with the name of police personnel to whom the paternity leave has been granted along with the days of leave; and

(c) the details of DD entry of weekly off taken by the S.I. and Inspector level officer of the above said district for the last six months ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) जी, हां श्री मान जी।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान नूहं जिले के किसी भी पुलिस कर्मचारी ने पितृत्व अवकाष के लिए आवेदन नही किया।

(ग) उप निरीक्षक और निरीक्षक तक के अधिकारी द्वारा नूहं जिलें में पिछले छः महीनों के अन्तर्गत साप्तहिक अवकाश की डी0डी0 प्रविष्टि का विवरण इस प्रकार से है।

विवरण

क्र0 न0	पद	नाम	नम्बर	थाना	रवानगी तिथि	डी. डी.	वापसी तिथि	डी. डी.
1.	निरीक्षक	करतार सिहं	107/HAP	यातायात	03.11.16	10	04.11.16	04
2.	निरीक्षक	अर्जुन राठी	--	रोजका मयो	08.01.17	14	09.01.17	12
3.	निरीक्षक	राम किषन	12/SR	नगीना	04.02.17	26	05.02.17	27
4.	उप निरीक्षक	विजय पाल	29/MWT	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	11.09.16	04	12.09.16	05
5.	उप निरीक्षक	राजिन्द्र	41/MWT	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	07.01.17	05	08.01.17	06
6.	उप निरीक्षक	जय चंद	01/MWT	अकेरा	21.01.17	03	22.01.17	17
7.	उप निरीक्षक	सुखबीर	--	नूह	16.08.16	04	17.08.16	22
8.	महिला निरीक्षक	कमलेश	377/FBD	महिला थाना	03.09.16	23	04.09.16	13
9.	महिला निरीक्षक	कमलेश	377/FBD	महिला थाना	11.09.16	10	12.09.16	03
10.	उप निरीक्षक	दलबीर	119/FBD	नूह	11.10.16	10	12.10.16	16
11.	उप निरीक्षक	दलबीर	119/FBD	नूह	02.11.16	12	03.11.16	16
12.	महिला निरीक्षक	कमलेश	377/FBD	महिला थाना	25.12.16	08	26.12.16	06
13.	महिला निरीक्षक	कमलेश	377/FBD	महिला थाना	08.01.17	08	09.01.17	08
14.	महिला उप निरीक्षक	विनिता	102/MWT	महिला थाना	07.12.16	08	08.12.16	12
15.	महिला निरीक्षक	कृष्णा देवी	212/G	महिला थाना	11.12.16	04	12.12.16	06
16.	महिला उप निरीक्षक	रेखा देवी	332/PWL	महिला थाना	26.12.16	07	27.12.16	04
17.	महिला निरीक्षक	कृष्णा देवी	212/G	महिला थाना	14.12.16	13	17.12.16	14

18.	उप निरीक्षक	सुरेश कुमार	451/H	तावडू	23.11.16	22	24.11.16	14
19.	निरीक्षक	ओम प्रकाष	SR/36	तावडू	28.12.16	24	29.12.16	13
20.	निरीक्षक	ओम प्रकाष	SR/36	तावडू	06.01.17	23	07.01.17	14
21.	उप निरीक्षक	जितेन्द्र	--	तावडू	28.01.17	24	29.01.17	06
22.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	10.10.16	06	11.10.16	05
23.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	15.10.16	03	16.10.16	03
24.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	23.10.16	07	24.10.16	05
25.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	01.11.16	04	02.11.16	07
26.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	08.11.16	03	09.11.16	03
27.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	14.11.16	04	15.11.16	07
28.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	19.11.16	07	20.11.16	09
29.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	26.11.16	09	27.11.16	07
30.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	01.12.16	10	02.12.16	08
31.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	07.12.16	03	08.12.16	03
32.	उप निरीक्षक	समसुदीन	85/SR	चौकी शहर पुनहाना	14.12.16	06	15.12.16	05
33.	उप निरीक्षक	मेहर सिहं	316/A	पुनहाना	03.09.16	24	04.09.16	15
34.	निरीक्षक	अशोक कुमार	--	पुनहाना	15.08.16	28	16.08.16	29
35.	निरीक्षक	अशोक कुमार	--	पुनहाना	17.09.16	20	18.09.16	24
36.	निरीक्षक	राम किषन	12/SR	पुनहाना	19.11.16	19	20.11.16	10
37.	निरीक्षक	जय प्रकाष	--	तावडू	18.09.16	21	20.09.16	20

एविडेन्स/रेस्ट

1.	निरीक्षक	कर्मबीर	A/38	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	02.11.16	03	05.11.16	03
2.	निरीक्षक	कर्मबीर	A/38	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	16.11.16	03	19.11.16	06
3.	निरीक्षक	रोहताष	167/H	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	04.01.17	03	06.01.17	04
4.	निरीक्षक	रोहताष	167/H	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	18.01.17	06	20.01.17	04
5.	उप निरीक्षक	सुखबीर	--	नूह	21.08.16	20	23.08.16	29
6.	उप निरीक्षक	सुखबीर	--	नूह	28.08.16	17	30.08.16	32
7.	उप निरीक्षक	सुखबीर	--	नूह	08.09.16	31	10.09.16	13
8.	उप निरीक्षक	सुखबीर	--	नूह	15.09.16	16	17.09.16	25
9.	उप निरीक्षक	सुखबीर	--	नूह	03.10.16	23	06.10.16	31
10.	उप निरीक्षक	सुखबीर	--	नूह	16.10.16	27	18.10.16	03
11.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स,	15.08.16	13	18.08.16	30

				नूह				
12.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	18.08.16	30	20.08.16	33
13.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	22.08.16	17	25.08.17	03
14.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	11.09.16	18	13.09.16	24
15.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	18.09.16	12	22.09.16	21
16.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	30.09.16	22	02.10.16	06
17.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	04.10.1.6	22	07.10.16	23
18.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	13.10.16	27	14.10.16	27
19.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	26.10.16	19	28.10.16	03
20.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	21.11.16	26	24.11.16	30
21.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	07.01.17	11	10.01.17	08
22.	निरीक्षक	विपिन कुमार	--	पुलिस लाईन्स, नूह	20.01.17	11	23.01.17	05
23.	महिला निरीक्षक	कृष्णा देवी	212/G	पुलिस लाईन्स, नूह	20.08.16	17	23.08.16	12
24.	महिला निरीक्षक	कृष्णा देवी	212/G	पुलिस लाईन्स, नूह	25.08.16	16	26.08.16	27
25.	उप निरीक्षक	दलबीर	119/FBD	पुलिस लाईन्स, नूह	22.11.16	25	24.11.16	32
26.	निरीक्षक	जय प्रकाष	--	पुलिस लाईन्स, नूह	13.02.17	21	15.02.17	15
27.	निरीक्षक	रोहताष	167/H	पूलिस स्टेषन, फिरोजपुर झिरका	20.11.16	16	21.11.16	17
28.	निरीक्षक	करतार सिहं	107/HAP	यातायात	16.11.16	16	17.11.16	11
29.	उप निरीक्षक	सुरेश कुमार	451/H	तावडू	27.11.16	19	29.11.16	10
30.	उप निरीक्षक	राम चंद्र	36/PWL	रोजका मयो	29.09.16	08	30.09.16	14
31.	उप निरीक्षक	राम चंद्र	36/PWL	रोजका मयो	23.10.16	23	24.10.16	11
32.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	रोजका मयो	07.01.17	04	08.01.17	21
33.	उप निरीक्षक	सुरेश कुमार	451/H	तावडू	11.10.16	17	13.10.16	11

ओ.एस.डी./रेस्ट

1.	महिला निरीक्षक	कृष्णा देवी	212/G	महिला थाना	29.11.16	03	01.12.16	12
2.	महिला उप निरीक्षक	रेखा देवी	332/PWL	महिला थाना	08.12.16	15	10.12.16	06
3.	महिला निरीक्षक	कमलेश	377/FBD	महिला थाना	20.10.16	14	22.10.16	03
4.	निरीक्षक	जय प्रकाष	--	तावडू	21.08.16	29	23.08.16	12
5.	निरीक्षक	ओम प्रकाष	SR/36	तावडू	23.10.16	28	25.10.16	02
6.	निरीक्षक	ओम प्रकाष	SR/36	तावडू	17.12.16	02	18.12.16	18
7.	उप निरीक्षक	मेहर सिहं	316/A	पुनहाना	15.08.16	25	18.08.16	25
8.	उप निरीक्षक	मेहर	316/A	पुनहाना	19.08.16	02	21.08.16	11

		सिहं						
9.	निरीक्षक	राम किषन	12/SR	पुनहाना	06.10.16	18	08.10.16	10
10.	निरीक्षक	राम किषन	12/SR	पुनहाना	03.11.16	40	05.11.16	15
11.	निरीक्षक	तरुण कुमार	RR/91	सी.आई.ए. नूह	22.08.16	07	23.08.16	06
12.	निरीक्षक	तरुण कुमार	RR/91	सी.आई.ए. नूह	27.10.16	10	28.10.16	06
13.	निरीक्षक	तरुण कुमार	RR/91	सी.आई.ए. नूह	06.02.17	07	10.02.17	09
14.	उप निरीक्षक	बच्चु सिहं	60/MWT	चौकी शहर, तावडू	29.01.17	15	01.02.17	03
15.	उप निरीक्षक	बच्चु सिहं	60/MWT	चौकी शहर, तावडू	13.02.17	19	16.02.17	03
16.	निरीक्षक	अर्जुन राठी	--	रोजका मयो	22.08.16	37	24.08.16	05
17.	निरीक्षक	अर्जुन राठी	--	रोजका मयो	09.12.16	03	11.12.16	09

हाई कोर्ट/रेस्ट

1.	उप निरीक्षक	राम चंद्र	36/PWL	रोजका मयो	24.11.16	29	26.11.16	32
2.	उप निरीक्षक	राम चंद्र	36/PWL	रोजका मयो	05.12.16	35	08.12.16	08
3.	निरीक्षक	तरुण कुमार	RR/91	सी.आई.ए. नूह	16.12.16	08	17.12.16	05
4.	निरीक्षक	करतार सिहं	107/HAP	यातायात	23.01.17	13	25.01.16	04
5.	उप निरीक्षक	सुरेश कुमार	451/H	चौकी शहर, नूह	25.08.16	17	27.08.16	06
6.	उप निरीक्षक	सुरेश कुमार	451/H	चौकी शहर, नूह	01.09.16	15	03.09.16	15
7.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	नगीना	18.01.17	21	25.01.17	18
8.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	नगीना	28.01.17	07	31.01.17	31
9.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	नगीना	02.02.17	11	05.02.17	26
10.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	नगीना	12.02.17	09	17.02.17	14
11.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	नगीना	19.02.17	15	21.02.17	16
12.	उप निरीक्षक	रमेश	547/H	नगीना	01.12.16	24	04.12.16	08
13.	उप निरीक्षक	जितेन्द्र	--	नगीना	11.12.16	15	14.12.16	10
14.	उप निरीक्षक	जितेन्द्र	--	नगीना	18.12.16	14	24.12.16	28
15.	उप निरीक्षक	कुलदीप सिहं	43/MWT	पिंगवाणा	16.10.16	15	20.10.16	04
16.	उप निरीक्षक	कुलदीप सिहं	43/MWT	पिंगवाणा	23.10.16	18	25.10.16	06
17.	निरीक्षक	रोहताष	167/H	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	22.01.17	05	25.01.17	04
18.	निरीक्षक	रोहताष	167/H	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	01.02.17	04	03.02.17	02
19.	निरीक्षक	कर्मबीर	A/38	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	22.11.16	05	24.11.16	05
20.	उप निरीक्षक	जय चंद	01/MWT	अकेरा	02.10.16	09	04.10.16	07
21.	उप निरीक्षक	जय चंद	01/MWT	अकेरा	06.12.16	12	08.12.16	07
22.	निरीक्षक	कर्मबीर	A/38	सी0एस0 स्टॉफ, नूह	05.10.16	04	08.10.16	04
23.	उप निरीक्षक	कुलबीर	--	नूह	31.08.16	25	03.09.16	11
24.	उप निरीक्षक	कुलबीर	--	नूह	06.09.16	33	08.09.16	22
25.	उप निरीक्षक	कुलबीर	--	नूह	20.09.16	32	23.09.16	05
26.	उप निरीक्षक	दीप चंद	1142/FBD	नूह	15.09.16	28	17.09.16	07
27.	उप निरीक्षक	दीप चंद	1142/FBD	नूह	18.09.16	22	21.09.16	08
28.	उप	दीप	1142/FBD	नूह	09.11.16	23	12.11.16	10

	निरीक्षक	चंद						
29.	उप निरीक्षक	दीप चंद	1142/FBD	नूह	14.11.16	15	18.11.16	05
30.	उप निरीक्षक	दीप चंद	1142/FBD	नूह	21.11.16	14	24.11.16	07
31.	उप निरीक्षक	दीप चंद	1142/FBD	नूह	01.12.16	16	04.12.16	05
32.	उप निरीक्षक	दीप चंद	1142/FBD	नूह	11.12.16	17	14.12.16	22
33.	निरीक्षक	अशोक कुमार	--	नूह	13.09.16	14	15.09.16	04
34.	निरीक्षक	अशोक कुमार	--	नूह	26.09.16	21	28.09.16	07
35.	निरीक्षक	अशोक कुमार	--	नूह	28.09.16	18	30.09.16	08
36.	निरीक्षक	अशोक कुमार	--	नूह	02.10.16	21	04.10.16	06
37.	महिला उप निरीक्षक	विनिता	102/MWT	महिला थाना	16.11.16	02	18.11.16	09
38.	महिला उप निरीक्षक	रेखा देवी	332/PWL	महिला थाना	15.12.16	03	17.12.16	05
39.	महिला उप निरीक्षक	रेखा देवी	332/PWL	महिला थाना	23.01.17	12	25.01.17	05
40.	महिला उप निरीक्षक	रेखा देवी	332/PWL	महिला थाना	05.02.17	15	07.02.17	06
41.	महिला उप निरीक्षक	विनिता	102/MWT	महिला थाना	15.12.16	12	17.12.16	15
42.	महिला उप निरीक्षक	राजमा देवी	101/MWT	महिला थाना	10.11.16	16	12.11.16	09
43.	महिला उप निरीक्षक	राजमा देवी	101/MWT	महिला थाना	16.11.16	24	18.11.16	08
44.	महिला उप निरीक्षक	राजमा देवी	101/MWT	महिला थाना	24.11.16	09	26.11.16	08
45.	महिला उप निरीक्षक	राजमा देवी	101/MWT	महिला थाना	15.12.16	05	16.12.16	14
46.	महिला उप निरीक्षक	राजमा देवी	101/MWT	महिला थाना	16.12.16	14	18.12.16	10
47.	महिला उप निरीक्षक	रेखा देवी	332/PWL	महिला थाना	08.02.17	17	11.02.17	12
48.	महिला उप निरीक्षक	राज कला	340/NNL	पूलिस स्टेषन, फिरोजपुर झिरका	18.12.16	24	21.12.16	08
49.	महिला उप निरीक्षक	राज कला	340/NNL	पूलिस स्टेषन, फिरोजपुर झिरका	18.01.17	25	21.01.17	12
50.	उप निरीक्षक	बलवंत	38/MWT	तावडू	18.01.16	15	21.01.16	09
51.	उप निरीक्षक	बलवंत	38/MWT	तावडू	29.08.16	26	01.09.16	09
52.	उप निरीक्षक	सुरेश कुमार	451/H	तावडू	10.11.16	26	13.11.16	14
53.	निरीक्षक	ओम प्रकाष	SR/36	तावडू	16.01.17	02	17.02.17	18
54.	उप निरीक्षक	मेहर सिहं	316/A	पुनहाना	30.09.16	11	08.10.16	15
55.	उप निरीक्षक	राजिन्द्र	41/MWT	पुनहाना	24.10.16	24	27.10.16	11
56.	उप निरीक्षक	राजिन्द्र	41/MWT	पुनहाना	08.11.16	23	15.11.16	02
57.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	पुनहाना	26.10.16	25	02.11.16	17
58.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	पुनहाना	10.11.16	14	13.11.16	04
59.	उप निरीक्षक	दलबीर	198/FBD	पुनहाना	19.11.16	22	23.11.16	10

Complaint Regarding Purchase of Input

417. Shri Karan Singh Dalal. : Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

(a) whether any complaint regarding scandal in the purchase of inputs by the Agriculture Department through HAFED, HLRDC and HSDC was received by the Government from Shri Ram Kanwar resident of Dulina, district Jhajjar during the year 2015-16; and

(b) if so, the details of the complaint and action taken by the Government on the complaint?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्री राम कंवर दुलीना की दो शिकायतें मिली। पहली शिकायत दिनांकित 16.11.2015 मुख्यमन्त्री विंडो (मुख्यमन्त्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ) पर की गई थी जोकि गेहूँ, बाजरा, सरसों, धान की सीधी बिजाई के प्रदर्शन के प्लाट के लिए कृषि सामग्री की खरीद में धांधली के बारे में थी। यह शिकायत विभाग द्वारा पूरी जांच के बाद दाखिल दफतर कर दी गई थी। तदानुसार कृषि विभाग द्वारा मुख्यमन्त्री विंडो (मुख्यमन्त्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ) पर शिकायत की वस्तुस्थिति अपलोड कर दी गई थी। परिणामस्वरूपः मामले का निपटान हो चुका है।

दुसरी शिकायत दिनांक 29.01.2016 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा बीज विकास निगम तथा हैफेड द्वारा जैविक खाद, एसीटोबैक्टर तथा वैस्टा खरपतवारनाशी कृषि सामग्री में अनियमितताओं तथा जैविक खाद की गुणवत्ता के बारे में थी। इस शिकायत की जांच अधिकारियों के समूह द्वारा की जा रही है जिसकी जांच रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Construction of Water Works

451. Shri Rajdeep Phogat. : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state the time by which

the construction work of the water works is likely to be started in village Hindol of Dadri Assembly Constituency ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) : श्रीमान् जी, गांव हिण्डोल में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना पहले ही वर्श 2010 से मौजूद है। इस जलघर योजना की 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने के पानी की आपूर्ति करने की क्षमता है। इस गांव में दूसरे जलघर योजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Vigilance Inquiry in Recruitment of Estate Officers.

462. Shri Pirthi Singh. : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that a vigilance inquiry was ordered on 21.05.2015 in respect of recruitment of Estate Officers made in the year 2013; if so, the details thereof together with the action taken by the Government ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां श्रीमान जी। श्री रवीन कादियान, निवासी रोहतक द्वारा दिनांक 20.11.2014 को एक शिकायत की गई कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पदा अधिकारी हुड्डा के पदो ंके लिये अंतिम चयन का परिणाम दिनांक 18.06.2013 को घोषित किया गया जिसमें उसे सफल घोषित किया गया था लेकिन बाद में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा उसके स्थान पर श्री दीपक कुमार रोल नं0 227 के चयन बारे 20.06.2013 को एक शुद्धिपत्र जारी कर दिया गया। श्री रवीन कादियान द्वारा चयन में भाई–भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की जांच किये जाने का अनुरोध किया गया था। सरकार द्वारा राज्य सतर्कता ब्यूरो हरियाणा के माध्यम से मामले की जांच किये जाने का निर्णय लिया गया था। तदानुसार राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा जांच क्रमांक 9, दिनांक 18.05.2015 पंचकूला पंजीकृत की गई थी। जांच क्रमांक 9, दिनांक 18.05.2015 पंचकूला की जांच रिपोर्ट राज्य सतर्कता ब्यूरो हरियाणा से प्राप्त हो गई है जो कि सरकार के विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं पॉवर के विषय में कुछ जानकारी सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से बार–बार कहा गया है कि आने वाले समय में पॉवर के रेट्स नहीं बढ़ायें जायेंगे बल्कि जहां तक संभव हो सकेगा इसमें कमी ही करने की कोशिश की जायेगी। वर्ष 2016 के सितम्बर माह मे 37 पैसे एफ.एस.ए. कम किया गया था जोकि पिछले 20 वर्ष के शासनकाल में किसी अन्य सरकार ने नहीं किया था। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) हमने पुनः एच.ई.आर.सी. को निवेदन किया चूंकि फ्यूल के रेट्स अब कुछ कम हो रहे हैं और कुछ घाटे को भी हम कम कर रहे हैं और उन्होंने हमारी बात को मान लिया है । मैं पूरे सदन को यह जानकारी दे रहा हूं कि अब पहली अप्रैल से एफ.एस.ए. को 50–60 पैसे कम कर दिया जाएगा । हम आगे भी यह प्रयत्न करेंगे कि बिजली के सिस्टम में कैसे सुधार हो । (विघ्न) मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक एफ.एस.ए. के नाम से जितनी महंगी बिजली खरीदी जा रही थी उसका एक पोर्शन एफ.एस.ए. में डाला जा रहा है । (विघ्न) आप मेरी बात को सुनिये । ये एफ.एस.ए. के नाम से हजारों करोड़ रूपये का घाटा छोड़कर गए थे । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि डिस्कॉम में घाटा नहीं था । वह घाटा इससे अलग था । ये 35,000 करोड़ रूपये का घाटा छोड़कर गये थे । हमने इसमें से उदय योजना के माध्यम से 26,000 करोड़ रूपये का कर्जा स्टेट गवर्नमैंट के ऊपर लिया है । इसके अतिरिक्त हमने उस कर्जे में से लगभग 3,000 करोड़ रूपये ब्याज का बचाया है । मैं पुनः कहता हूं कि ये एफ.एस.ए. अलग से छोड़कर गये थे उस एफ.एस.ए. को कवर करते–करते हमने यह पैसा कवर किया है क्योंकि पहले 1–1.24 रूपये प्रति मिनट तक एफ.एस.ए. का खर्च लिया जाता था । अब हम इसे 50–60 पैसे और कम करेंगे । हमने 37 पैसे एफ.एस.ए. पहले ही कम कर दिया है । हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस एफ.एस.ए. को आगे भी कम करें । हम पिछले एफ.एस.ए. को खत्म करेंगे । नये एफ.एस.ए. के जो चार्जिज होंगे वे उसमें जोड़े जा सकेंगे । अब चूंकि कोयले के रेट कम हुए हैं और बाकी चीजों के फ्यूल के रेट कम हुए हैं तो हम उस घाटे को कम करते–करते इस एफ.एस.ए. के रेट को कम कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बिजली के बिल में हाउस टैक्स और डीजल के नाम

से एक कॉलम है जिसमें लोगों से पैसे वसूले जाते हैं । मेरा निवेदन है कि इनको चैक करा लिया जाए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम उसे चैक करा लेंगे । इसके अतिरिक्त म्यूनिसिपल टैक्स उसमें जरूर लगता है और वह बहुत पुराने समय से वर्ष 1991 से लगा आ रहा है । (विघ्न) म्यूनिसिपैलटीज को और ग्राम पंचायतों को कुछ सैस उसमें से जाए ताकि म्यूनिसिपैलटीज की स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किया जा सके । अब धीरे–धीरे गांव में भी स्ट्रीट लाइट्स लगाने की प्रथा शुरू हो रही है । गांव में पंचायतों का कॉमन बिल काफी ज्यादा आता है । इसलिए सैस का पैसा उसके लिए थोड़ा बहुत डाला जाए, ताकि स्थानीय संस्थाओं को बिजली के बिलों में लाभ मिले इसलिए अगर मात्र इसका थोड़ा–थोड़ा परसेंट उसमें दे दिया जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । (विघ्न) इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि सरकार की ओर से 26 हजार करोड़ रूपये का ऋण को ले लिया गया है जिसके कारण से डिस्कॉम को 3000 रूपये का सालाना इंट्रस्ट देना पड़ता है । इससे इंट्रस्ट की बचत भी हुई है । इससे वह घाटा भी कम होगा और हम एच.ई.आर.सी. से कहकर कोशिश करेंगे कि इन बिजली के बिलों को और भी कम किया जाए । कुल मिलाकर हम अपने वायदे पर कायम रहेंगे और आगे हम बिजली के बिलों को बढ़ने नहीं देंगे ।

.....

वर्ष 2017–2018 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष राज्य का वित्त वर्ष 2017–18 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

2. राज्य के गठन के स्वर्ण जयंती वर्ष में बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं लगातार तीसरी बार प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर सरकार की पिछले दो वर्ष की उपलब्धियों और आगामी तीन वर्ष में विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार की परिकल्पना एवं रणनीति पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

3. वित्त वर्ष 2016–17 देश के आर्थिक इतिहास में एक अनूठा वर्ष है, जो वर्ष 2017–18 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए संविधान (एक

सौ एक वां संशोधन) अधिनियम 2016 के पारित होने और 500 रुपये एवं 1000 रुपये के विशिष्ट बैंक नोटों का प्रचलन बंद करने के रूप में दो प्रमुख नीतिगत सुधारों का साक्षी रहा है। निःसंदेह, इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था विशाल, स्वच्छ एवं अधिक सुव्यवस्थित बनेगी।

4. इसी प्रकार, केन्द्र में बजटीय प्रक्रिया में तीन सुधार किए गए हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2017–18 से योजना एवं गैर–योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करना, आम बजट के साथ रेल बजट का विलय और बजट को पारम्परिक समय से पहले पेश करना शामिल है ताकि इसके अनुमोदन की प्रक्रिया को नए वित्त वर्ष के आरंभ होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। राज्य सरकार और हरियाणा के लोगों की ओर से, मैं इन महत्वपूर्ण पहलों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत के वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूँगा।

5. हालांकि, राष्ट्रीय जीडीपी विकास दर पर वैश्विक मंदी का क्षणिक प्रभाव रहा क्योंकि वर्ष 2015–16 के 7.9 प्रतिशत की तुलना में चालू वित्त वर्ष में यह कम होकर 7.1 प्रतिशत हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अगले वर्ष इसका प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 में वृद्धि दर

7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैश्विक मंच पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकते सितारे के समान है, क्योंकि वैश्विक मंदी के दौर में भी यह तेजी से उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही।

6. केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर, हमने भी व्यय के योजना एवं गैर–योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करने और बजट को राजस्व एवं पूंजीगत वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है, जो क्षेत्रवार आबंटन का समग्र अवलोकन करवाएगा, जिससे विभागों को संसाधनों का इष्टतम आबंटन हो सकेगा। इस बार, मैंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निधि प्रवाह बारे एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से संसाधनों के आबंटन को यथासम्भव ग्रामीण और शहरी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का भी प्रयास किया है।

विगत प्रदर्शन की समीक्षा

7. माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट है, इसलिए पिछली सरकार के प्रदर्शन की तुलना में गत दो वर्षों के दौरान हमारे प्रदर्शन की समीक्षा करने का भी यह उचित समय है।

आर्थिक स्थिति – सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में राज्य ने सभी आर्थिक एवं राजकोषीय मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उदाहरण के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने स्थिर मूल्यों (2011–12) पर वर्ष 2014–15 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2015–16 में 9.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2016–17 में भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, वर्ष 2017–18 में यह 9.0 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है। पिछली सरकार के गत पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान जीएसडीपी विकास दर कभी भी 9.0 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाई। यह वर्ष 2010–11 में 7.4 प्रतिशत, 2011–12 में 8.0 प्रतिशत, 2012–13 में 7.7 प्रतिशत, 2013–14 में 8.2 प्रतिशत और 2014–15 में 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर अखिल भारतीय जीडीपी विकास दर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक बनी हुई है।

9. वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 5.8 प्रतिशत के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 4.0 प्रतिशत थी। प्रति व्यक्ति आय की विकास दर वर्ष 2015–16 में 6.6 प्रतिशत के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में 7.5 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति आय की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 5.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

10. इसी प्रकार, राज्य के प्राथमिक क्षेत्र (कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र) ने वर्ष 2014–15 में 2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2015–16 में

3.2 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है। वर्ष 2016–17 में इसके 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी प्रकार, द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग) ने

वर्ष 2015–16 में 7.7 प्रतिशत की ठोस वृद्धि दर्ज की है, जबकि वर्ष 2014–15 में यह मात्र 2.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 में इस क्षेत्र की विकास दर 6.1 प्रतिशत अनुमानित है। तृतीयक (सेवा) क्षेत्र ने वर्ष 2015–16 में 10.9 प्रतिशत की आकर्षक विकास दर दर्शायी है, जबकि वर्ष 2014–15 में यह 10.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2016–17 में इस क्षेत्र की विकास दर 10.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

11. सकल राज्य मूल्य संवर्धन (जीएसवीए) का संयोजन सेवा क्षेत्र के प्रति राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, जोकि परिपक्व एवं विकासशील अर्थव्यवस्था का संकेत है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन के संयोजन के विश्लेषण से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2014–15 में 49.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 50.7 प्रतिशत और वर्ष 2016–17 में 51.7 प्रतिशत हुई है। द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी गत तीन वर्षों के दौरान लगातार कमोबेश 30 से 31 प्रतिशत के बीच रही। तदानुसार, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट का रुख रहा, जो वर्ष 2014–15 में 19.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 18.3 प्रतिशत और 2016–17 में 18.1 प्रतिशत रही।

राज्य वित्त – राजकोषीय मापदंड

12. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन नीतियों का अनुसरण करते हुए, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हावी रहे बढ़ते घाटा मानकों को बदलने में सक्षम हुई है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 में राजस्व घाटा, जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.90 प्रतिशत था, वर्ष 2015–16 में कम होकर 1.60 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2016–17 में इसके 1. 33 प्रतिशत रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए, मैंने इसे एक प्रतिशत से भी कम करने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2019–20 के अंत तक, मेरा लक्ष्य इसे शून्य पर लाने का है।

13. राजकोषीय घाटा 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित की गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर रहा। वर्ष 2015–16 में, राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.92 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2016–17 में इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.49 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। आगामी वर्ष के दौरान, इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.61 (उदय के बिना) से 2.84 प्रतिशत (उदय के साथ) के बीच रहने की संभावना है।

14. सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात पर ऋण 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर रहा। यह 'उदय' के बिना वर्ष 2014–15 में 16.21 प्रतिशत,वर्ष 2015–16 में 17.40 प्रतिशत और वर्ष 2016–17 (संशोधित अनुमान) में 18.08 प्रतिशत तथा 'उदय' के साथ वर्ष 2015–16 में 20.96 प्रतिशत और

वर्ष 2016–17 (संशोधित अनुमान) में 22.82 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 में 'उदय' के बिना 18.74 प्रतिशत और 'उदय' के साथ 22.93 प्रतिशत रहने की संभावना है।

कुल राजस्व प्राप्तियां (टीआरआर)

15. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2016–17 में 11.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2015–16 में ये 9.80 प्रतिशत और वर्ष 2014–15 में 9.33 प्रतिशत थी। यह एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका राज्य संसाधनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

16. संशोधित अनुमान 2016–17 के लिए, कुल राजस्व प्राप्तियां 60327.09 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें 45087.63 करोड़ रुपये (74.74 प्रतिशत) की कर राजस्व प्राप्तियां और 15239.46 करोड़ रुपये (25.26 प्रतिशत) की गैर–कर राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।

17. वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों में, मैंने 68810.88 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित की हैं, जिनमें 51711.52 करोड़ रुपये की कर प्राप्तियां और 17099.36 करोड़ रुपये का गैर–कर प्राप्तियां शामिल हैं। यह वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 14.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017–18 में, कुल राजस्व प्राप्तियां, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 11.12 प्रतिशत रहने की संभावना है।

कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान

18. कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान वर्ष 2014–15 में 16.98 प्रतिशत था, जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 17.42 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वर्ष 2016–17 में यह घटकर 15.94 प्रतिशत रह गया है।

वर्ष 2017–18 में इसके लगभग 16.36 प्रतिशत रहने का अनुमान है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)**

पूंजीगत खर्च

19. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, वर्तमान सरकार कुल खर्च में पूंजीगत खर्च का अनुपात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ष 2015–16 के 6780.12 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च के समक्ष, संशोधित अनुमान 2016–17 में 9.6 प्रतिशत बढ़कर यह 7432 करोड़ रुपये हो गया। आगामी वित्त वर्ष 2017–18 के लिए, मैं इसे संशोधित अनुमान 2016–17 पर दोगुना करके 14932 करोड़ रुपये

करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा 4725 करोड़ रुपये खर्च करने की सम्भावना है। इसलिए, वर्ष 2017–18 में कुल पूंजीगत खर्च 19657 करोड़ रुपये अनुमानित है।

ग्रामीण–शहरी वर्गीकरण

20. मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में 8 विभागों द्वारा किये गये खर्च को चिन्हित करने का प्रयास किया है। वर्ष 2016–17 में, मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना 91 प्रतिशत परिव्यय (7296 करोड़ रुपये) खर्च करने का अनुमान है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 88 प्रतिशत (3870 करोड़ रुपये), महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 87 प्रतिशत (1050.52 करोड़ रुपये), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 70 प्रतिशत (2947 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 43 प्रतिशत (331 करोड़ रुपये), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 38 प्रतिशत (513 करोड़ रुपये), इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 33 प्रतिशत (28 करोड़ रुपये) तथा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 17 प्रतिशत (288 करोड़ रुपये) खर्च किये जाने की संभावना है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सिंचाई विभाग को किया गया व्यापक आबंटन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। संभावना है कि आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आबंटन में और वृद्धि होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा

21. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसई) राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में हुए सुधार के फलस्वरूप न केवल लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि इनके घाटे में भी कमी आई है।

22. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 22 उपक्रमों में से 15 उपक्रमों ने वर्ष 2013–14 में 13 उपक्रमों की तुलना में वर्ष 2015–16 में 299.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के इन 13 उपक्रमों द्वारा 803.92 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 में नौ से कम होकर 2015–16 में छः रह गई। इनका घाटा वर्ष 2013–14 में 3806.38 करोड़ रुपये से 78.67 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2015–16 में 811.63 करोड़ रुपये रह गया।

23. इसी प्रकार, सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रम भी अपने घाटे को कम करने में सफल रहे हैं, जिससे सुधार के संकेत मिले हैं। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013–14 में 13 से कम होकर 2015–16 में 11 रह गई तथा इनका घाटा वर्ष 2013–14 में 435.39 करोड़ रुपये से कम होकर 2015–16 में 407.70 करोड़ रुपये रह गया। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या पांच से बढ़कर छः हुई है। कुल संचित लाभ वर्ष 2015–16 में बढ़कर 468.02 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2013–14 में यह 451.07 करोड़ रुपये था।

24. विशेष कानूनों के तहत पंजीकृत पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है, क्योंकि ये उपक्रम अपने घाटे को वर्ष 2013–14 में 398. 79 करोड़ रुपये से कम करके 2015–16 में 39.43 करोड़ रुपये करने में सक्षम रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन सुधारने तथा उनके संचित घाटे को कम करने की दिशा में काफी कुछ किया जाना है।

बजट 2017–18

25. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इस समय हम वर्ष 1966 में अपने राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। महोदय, इस शुभ वर्ष में, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए मैं 102329.35 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 90412.59 करोड़ रुपये पर 13.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब खाद्यान्न खरीद कार्यों को छोड़कर, बजट ने एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। महोदया, 102329.35 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय में 22393.51 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च और 79935.84 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय शामिल है जोकि क्रमशः 21.88 प्रतिशत और 78.12 प्रतिशत है।

26. वर्तमान बजट हमारे प्रदेश को भारतीय संघ की एक जीवंत, गतिशील और उभरती इकाई के रूप में रूपांतरित करने के माननीय मुख्यमंत्री जी के उस विजन पर आधारित है, जहां खेतों में फसलें लहलहा रही हों, उद्योग के पहिये निर्बाध रूप से गतिशील हों, कोई भी अपने–आपको वंचित महसूस न करे, लोगों में संतुष्टि का भाव हो, युवा गर्व की भावना से ओत–प्रोत हों और अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समान अवसर मिलें, बल्कि वे सशक्त भी महसूस करें। 'अंत्योदय' और 'सरकार कम से

कम–सुशासन अधिकतम' ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, जो हरियाणा को रहने के लिये एक बेहतर स्थान बनाते हैं। इस विजन को पूरा करने के उद्देश्य से नौ प्राथमिकता क्षेत्रों नामतः (प) कृषि, (पप) ग्रामीण विकास, (पपप) शहरी विकास, (पअ) अवसंरचना, (अ) शिक्षा और आईटी शासन, (अप) स्वास्थ्य, (अपप) महिला सशक्तिकरण, (अपपप) युवा और (गप) संस्कृति के विकास पर आधारित एक रणनीति और कार्य योजना तैयार की गई है।

27. हमने प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार–मुक्त शासन उपलब्ध करवा कर व्यवस्था–परिवर्तन के एक नए युग का सूत्रपात किया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) इस दिशा में एक प्रमुख कदम है, जिसके तहत विभिन्न कल्याण सबसिडी वाली योजनाओं के तहत अपात्र लाभार्थियों को निकालकर अब तक लगभग 571 करोड़ रुपये की बचत की गई है। पढ़ी–लिखी पंचायतों का चुनाव, एचसीएस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक सरकारी नौकरियों में पूर्णतः योग्यता के आधार पर पारदर्शी भर्ती, ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति, सीएम विंडो के माध्यम से लोगों की शिकायतों का प्रभावी निवारण, समय पर, पारदर्शी और परेशानी–मुक्त तरीके से कम्प्यूटर के एक क्लिक पर 24 विभागों की लगभग 170 ई–सेवाओं का प्रावधान, शासन में बदलाव के कुछ महत्तवपूर्ण उदाहरण हैं।

28. ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च की बढ़ोतरी, चरणबद्ध तरीके से बजटीय प्रावधानों के साथ विभिन्न विभागों के कुछ कार्यों को हस्तांतरित करके पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण, शासन में सुधारों का सूत्रपात, डिजिटल हरियाणा पर बल और मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर बजट में विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

नई योजनाएं/पहल

29. स्वर्ण जयंती वर्ष में, शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर तीन वर्ष के अंदर चरणबद्ध ढंग से आवश्यक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवा कर 3000 से 10,000 तक की आबादी वाले लगभग 1500 गांवों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय से, मैं हरियाणा के महान नेता रहबरे आज़म दीनबंधु स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर ''दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना' के नाम से एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह योजना नाबार्ड से

वित्त पोषित होगी। वर्ष 2017–18 के लिए, मैं इस योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

30. इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना के सृजन और मौजूदा अवसंरचना के रख–रखाव के लिए, मैं हरियाणा के महान नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सेन के नाम से नई योजना ''मंगल नगर विकास योजना'' शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिए आरंभ में 1000 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

31. भारत सरकार द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के निर्दिष्ट बैंक नोटों को बंद करने के ऐतिहासिक निर्णय से व्यवस्था में काले धन और भ्रष्टाचार की बुराई पर अंकुश लगाने के लिए नकद लेन–देन को हतोत्साहित करने और कैशलेस लेन–देन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। आज भारत एक व्यापक डिजिटल क्रांति की दहलीज पर है। हरियाणा इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सकता। इसलिए, सरकार प्रदेश में औपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड जैसे डिजिटल तरीकों और अन्य साधनों के माध्यम से कैशलेस लेन–देन को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि 5000 रुपये से अधिक के सभी सरकारी भुगतान केवल डिजिटल पद्धति से किए जाएंगे। भीम एप्प के माध्यम से बिजली निगमों के बिल भुगतान और अन्य सरकारी भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 रुपये होगी।

32. अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्बाध एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ''कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना'' शुरू करने की संभावनाएं तलाशने की इच्छुक है।

33. राज्य सरकार द्वारा भवनों, खाली भूमियों, अवसंरचना आदि जैसी सृजित अचल भौतिक परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में मरम्मत और रख–रखाव के अभाव के कारण कमी आई है। इस तरह की भौतिक परिसंपत्तियों को उचित रख–रखाव की ही नहीं बल्कि नियमित अंतराल पर सुदृढ़ किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि उनकी पूरी क्षमता का लाभ लिया जा सके। इसलिए, मैं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक समर्पित **''परिसम्पत्ति संवर्धन कोष''** (Asset Augmentation Fund) सृजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, राज्य संसाधनों का परिसम्पत्ति मानचित्रण करने तथा सभी

सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का एक रजिस्टर तैयार करने के लिए राजस्व विभाग में एक समर्पित परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ (Asset Management Cell) बनाया जा रहा है।

क्षेत्रवार आबंटन

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

34. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, खाद्य सुरक्षा के मामले में किसान व मजदूर देश की रीढ़ हैं। इसलिए, उन्हें एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना जरूरी है, जहां उन्हें आय सुरक्षा मिले। राज्य के किसान कृषि क्षेत्र में एक सुखद बदलाव लेकर आए हैं जोकि वर्ष 2014–15 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की 2.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि से 2015–16 में 3.2 प्रतिशत और 2016–17 में 7.0 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मक वृद्धि के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार द्वारा उठाए गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014–15 में 152.36 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2015–16 में 163.33 लाख मीट्रिक टन हो गया, जोकि 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2016–17 के लिए 174.50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

35. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और उनके समग्र विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार सात कार्य बिंदुओं पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। ये कार्य बिंदु हैं, (i) प्रभावी सिंचाई पद्धतियां, (ii) गुणवत्ता आदानों – बीजों और उर्वरकों का प्रावधान, (iii) कटाई उपरांत नुकसान की रोकथाम, (iv) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देना, (v) ई–बाजार की स्थापना, (vi) फसल बीमा और (vii) पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन इत्यादि जैसी संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना।

36. मृदा में मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए, राज्य सतत् आधार पर मृदा परीक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। वर्तमान में, राज्य में 34 मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) संचालित हैं। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान 50 मिनी मृदा परीक्षण इकाइयों की खरीद की गई है। इसके अतिरिक्त, एक नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कैथल के गुहला चीका में स्थापित की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत, 11.80 लाख मृदा

नमूने एकत्र किये गये, जिनमें से पाँच लाख से अधिक मृदा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

37. सरकार ने वर्ष 2030 तक, 15 वर्षों में बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र को दोगुना करने और उत्पादन को तीन गुणा करने के लिए ''बागवानी विजन'' तैयार किया है। सरकार ने 140 फसल कलस्टरों में 340 ''बागवानी गांव'' घोषित किए हैं, जिनके लिए फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी) तैयार किया गया है।

38. करनाल में महाराणा प्रताप के नाम पर एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। सरकार की राज्य के प्रत्येक जिले में ''उत्कृष्टता केन्द्र'' स्थापित करने की योजना है। करनाल, सिरसा और कुरुक्षेत्र में तीन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। एक अन्य केन्द्र शाहाबाद, कुरुक्षेत्र में मार्च 2017 तक पूरा हो जाने की संभावना है। झज्जर और नारनौल में अन्य दो केन्द्रों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

39. केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली को सुचारू, पारदर्शी और किसानों व आढ़तियों के अनुकूल बनाने के लिए ई–एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना के तहत एक ई–मार्केट प्लेटफार्म शुरू किया है। राज्य में

37 मंडियों को इस प्लेटफार्म के साथ जोड़ा जा चुका है और शेष को शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा।

40. किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा में गन्ना किसानों को गन्ने का 320 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है जोकि देश में सर्वाधिक है। राज्य में पहली बार सरकारी एजेंसियों द्वारा मूंग दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई।

41. हमारा प्रयास है कि किसान खेती के साथ–साथ डेरी फार्मिंग का कार्य भी करें ताकि उनकी अतिरिक्त आय सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए, देसी गायों की मिनी डेरी इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को

50 प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है। पशुधन पालकों के लिए पशुधन बीमा योजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लोगों के पशुधन को निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है।

42. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र वर्तमान सरकार के लिए विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। मैं, वर्ष 2017–18 के दौरान कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए

3206.01 करोड़ रुपये का आबंटन प्रस्तावित करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 2698.80 करोड़ रुपये से 18.79 प्रतिशत अधिक है। इसमें कृषि के लिए 1516.01 करोड़ रुपये, पशुपालन के लिए 746.88 करोड़ रुपये, बागवानी के लिए 396.93 करोड़ रुपये, वनों के लिए 457.62 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन के लिए 88.57 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

सिंचाई और जल संसाधन

43. वर्तमान सरकार ने प्रदेश में पानी की हर बूंद का इष्टतम उपयोग और संरक्षण करने के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ सिंचाई के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए हैं।

44. ''हर खेत को पानी'' के विज़न को साकार करने की दिशा में, जेएलएन उठान सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पम्प घरों और नहरों की क्षमता को सुधारने के लिए 143 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका कार्य वर्ष 2017–18 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिसंबर, 2016 में पिहोवा में 13 जिलों के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रदर्शन की 25 करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया।

45. वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी, हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, पृथला डिस्ट्रीब्यूटरी, खनौरी माइनर, जाखौली डिस्ट्रीब्यूटरी, टोहाना डिस्ट्रीब्यूटरी, नई उरलाना माइनर, जहांगीरपुर माइनर, पहाड़ीपुर माइनर, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी, बसई डिस्ट्रीब्यूटरी आदि के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। विभाग ने चरणबद्ध तरीके से प्रमुख मरम्मत कार्यों, रि–मॉडलिंग और पुनरोद्धार हेतु 7500 जलमार्गों की पहचान की है।

46. इसके अलावा, राज्य सरकार ने नाबार्ड की वित्तीय सहायता से वित्त वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान 125 चैनलों और 400 जलमार्गों के पुनरोद्धार की योजना बनाई है।

47. सरकार सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने तथा रावी–ब्यास के हरियाणा के यथोचित हिस्से का पानी लेने के लिए कृत–संकल्प है। राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई, जो गत 12 वर्षों से अधिक समय से लंबित थी, पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवम्बर, 2016 को हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि पंजाब वर्ष 2002/2004 के फैसले तथा निर्णय को रद्द और 31 दिसम्बर, 1981 के समझौते को समाप्त नहीं कर सकता। पंजाब

में एसवाईएल नहर के शेष भाग को शीघ्र पूरा करवाने और प्रदेश के लोगों को चिरलम्बित न्याय दिलवाना सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा ने 28 नवम्बर, 2016 को माननीय राष्ट्रपति महोदय को, उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए एक ज्ञापन सौंपा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 फरवरी, 2017 को दोहराया है कि न्यायालय द्वारा 30 नवम्बर, 2016 को पारित अंतरिम आदेश, आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए, मैं वर्ष 2017–18 में विशेष तौर पर 100 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस गरिमामयी सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि एसवाईएल नहर को बनवाने के लिये अगर 1000 करोड़ रुपये की भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी व्यवस्था करेंगे।

48. वर्ष 2017–18 के लिए, मैं सिंचाई और जल संसाधनों के लिए परिव्यय को संशोधित अनुमान 2016–17 के 2397.68 करोड़ रुपये से 13.62 प्रतिशत बढ़ाकर 2724.26 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

ग्रामीण विकास

49. राज्य सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए ''ग्रामोदय से भारत उदय'' कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने गांवों को आदर्श गांव बनाकर गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

50. ''स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना'' के प्रथम चरण में, 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले गांवों में सुनियोजित ढंग से सभी प्रकार की शहरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह योजना 1461 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक पांच वर्ष के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

51. पहली बार, ''स्वर्ण जयंती विकास निधि'' योजना के तहत आबादी के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को वार्षिक आधार पर विकास कार्यों के लिए सुनिश्चित निधि पैकेज हस्तांतरित किया गया है।

52. हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों के सहयोग से, राज्य ने वर्ष 2016–17 में 14 जिलों के लिए खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार का नवम्बर, 2017 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य है।

53. गांवों में आधुनिक सुविधाओं से लैस ग्राम सचिवालय और अटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें भारतनैट परियोजना के माध्यम से कनैक्टिविटी

प्रदान की जा रही है। अब तक राज्य के 100 गांवों में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

54. राज्य सरकार कार्यों, अधिकारियों और निधि के मामले में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षित जनप्रतिनिधियों का चुनाव इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया है। ग्राम पंचायत के पंच से लेकर जिला परिषद् के अध्यक्ष तक का मानदेय प्रतिमाह 400 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक बढ़ाया गया है।

55. मैं वर्ष 2017–18 के दौरान ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 4963.09 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 3167.55 करोड़ रुपये पर 56.69 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है।

सामाजिक क्षेत्र

स्वास्थ्य

56. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारा लक्ष्य ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः'' का है। इसलिए, राज्य सरकार ने प्रदेश में सस्ती, सुविधाजनक और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी है। सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। छः जिला अस्पतालों तथा तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में पीपीपी मोड पर एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की गई हैं। पांच और जिला अस्पतालों के सम्बन्ध में इन मशीनों की स्थापना के लिए आदेश पत्र जारी हो चुका है। पहली बार चार जिलों में डायलिसिस सेवाएं शुरू हुई हैं तथा अन्य 10 जिलों में स्थापित की जा रही हैं। चार जिला अस्पतालों नामतः पंचकूला, गुरुग्राम, अम्बाला छावनी और फरीदाबाद में अत्याधुनिक कैथ–लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

57. राज्य सरकार की परिकल्पना प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की है। भिवानी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। कुटैल, करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय में 750 बिस्तर वाला 'अत्याधुनिक' मल्टी स्पेशिलिटी और सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल होगा। जींद में वर्ष 2017–18 में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) द्वारा

कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल का निरीक्षण किया जा चुका है और इसमें शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में 100 सीटों के लिए एमबीबीएस के पहले बैच के दाखिले होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े जिले नूह के लोगों को बेहतर दंत चिकित्सा सुविधाएं तथा दंत शिक्षा मुहैया करवाने के लिए शहीद हसन खाँ मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहड़ में एक डेंटल कालेज भी स्थापित किया जाएगा।

58. मैं वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3839.90 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 में 3323.95 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 15.52 प्रतिशत की वृद्धि है।

शिक्षा

59. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, राज्य सरकार युवा पीढ़ी को शिक्षित, सदाचारी, स्वस्थ और कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के अतिरिक्त, शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दे रही है।

60. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सरकार ने शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सार्वभौमिक पहुंच के अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता भी मायने रखती है जिसके लिए सरकार स्कूलों में शैक्षणिक माहौल में सुधार पर बल दे रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य में गुणवत्ता सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सीखने के अंतर को पाटना और यह सुनिश्चित करना है कि पांच वर्षों में प्राथमिक कक्षाओं के कम से कम 80 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड स्तरीय दक्षता प्राप्त कर लें। ''अध्ययन अभिवृद्धि कार्यक्रम (स्मंतदपदह म्दींदबमउमदज च्तवहतंउउम)'' के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए सुधारात्मक कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही, अध्यापक प्रशिक्षण कोर्सों के माध्यम से अध्यापकों की क्षमता बढ़ायी जा रही है।

61. स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल टूल्स का लाभकारी उपयोग किया जा रहा है। इस लक्ष्य की दिशा में, विभाग ने स्कूल प्रशासन में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और प्रशासनिक तथा शैक्षणिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। शिक्षकों का न्यायोचित और मांग

आधारित वितरण सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, अपने कर्मचारियों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य के प्रति संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए, एमआईएस आधारित ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति लागू की गई है। शिक्षक स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 12843 पीजीटी और 22588 पीआरटी को स्थानांतरित किया गया है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को सभी प्रोत्साहन, छात्रवृत्तियां और अन्य लाभ आधार से जुड़े खातों के माध्यम से दिये जा रहे हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड के लिए पंजीकरण किया जा चुका है।

62. भर्ती निकायों के माध्यम से नियमित कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, विभाग ने स्कूलों में अध्यापकों की तत्काल तथा अपरिहार्य कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं लेने के लिए 'सुगम शिक्षा' स्कीम बनाई है। इसी प्रकार, स्कूलों की सम्पूर्ण स्वच्छता में सुधार लाने के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में 'स्वच्छ प्रांगण' योजना शुरू की है।

63. वर्ष 2016–17 के दौरान 33 राजकीय मिडल एवं हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा दिया गया और दो नए स्कूल भी खोले गए। इन सभी स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों की शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं और इन विषयों के लिए अध्यापकों के पद भी स्वीकृत किए गए हैं।

64. सरकार उच्चतर शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर जरूरतमंदों और महिलाओं तक उच्चतर शिक्षा की न्यायसंगत, सस्ती और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विस्तार पर भी पर्याप्त बल दिया गया है।

65. मैं बजट अनुमान 2017–18 में शिक्षा (मौलिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) के लिए 14005 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जोकि संशोधित बजट प्रावधान 2016–17 के 11825.67 करोड़ रुपये पर 18.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तकनीकी शिक्षा

66. राज्य सरकार ने इंडरी (नूंह), मालब (नूंह), छपार (दादरी), मंडकोला (पलवल) और शेरगढ़ (कैथल) में पांच नए बहुतकनीकी संस्थानों का निर्माण किया है। इसके अलावा, गांव नीमका, (फरीदाबाद) में बहुतकनीकी संस्थान के साथ–साथ एक टूल

रूम/टैक्नालॉजी सेंटर चलाने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

67. पंचकूला और रेवाड़ी में क्रमशः 38 करोड़ रुपये और 16.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो नए राजकीय बहुतकनीकी–सह–बहु कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

68. राज्य सरकार ने सिलानी केशो, झज्जर और जैनाबाद, रेवाड़ी में दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए हैं। इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। वर्ष 2017–18 में आईआईआईटी, सोनीपत और एनआईएफटी, पंचकूला का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

69. भारत सरकार ने ऐसे जिलों, जिनमें बहुतकनीकी संस्थान नहीं हैं या इनकी कमी हैं, में सात बहुतकनीकी स्वीकृत किए हैं और प्रत्येक के लिए 12.30 करोड़ रुपये की अनुदान स्वीकृत की है। चीका (कैथल) और लिसाणा (रेवाड़ी) में बहुतकनीकी स्थापित कर दिए गए हैं, हथनीकुंड (यमुनानगर), उमरी (कुरुक्षेत्र), जाटल (पानीपत) और धांगड़ (फतेहाबाद) में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, तथा नानकपुर (पंचकूला) में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के तहत 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सढ़ौरा, यमुनानगर में राजकीय बहुतकनीकी स्थापित किया जा रहा है।

70. मैं बजट अनुमान 2017–18 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 487.84 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

71. राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर ''हरियाणा कौशल विकास मिशन'' शुरू किया है। इसके तहत हर वर्ष लगभग 1.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पलवल के दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

72. वर्ष 2017–18 में गांव नोहनी (अंबाला), घरौंडा (करनाल), राई (सोनीपत), इंद्री (करनाल), सतनाली (महेंद्रगढ़), सिकरोना (फरीदाबाद), मुशैदपुर (गुरुग्राम), खेवड़ा (सोनीपत), कादमा (भिवानी), सेहलंगा (महेंद्रगढ़), बराणा (पानीपत), पलवल, फरीदाबाद, हसनपुर (अंबाला) और जीवन नगर (सिरसा) में

15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) स्कीम के तहत 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, टंकड़ी (रेवाड़ी), नलवा (हिसार), जुलाना (जींद), कलायत (कैथल) और मुंडलाना (सोनीपत) के विस्तार का भी प्रस्ताव है।

73. मैं बजट अनुमान 2017–18 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 487.39 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

खेल एवं युवा मामले

74. राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा शारीरिक गतिविधियां और खेल नीति–2015 बनाई है। सभी गांवों और शहरों में योगशालाएं स्थापित करने के उद्देश्य से योग एवं योगशाला नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है।

75. सरकार ने हरियाणा से ओलंपिक तथा पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 2.50 करोड़ और प्रत्येक प्रतिभागी को 15 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

76. मैं युवाओं से उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानने और राज्य एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा का योगदान देने के लिए आगे आने का आग्रह करता हूँ। मैं बजट अनुमान 2017–18 में खेलों के लिए 535.36 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 336.49 करोड़ रुपये की तुलना में 59.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सक्षम योजना

77. हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर, 2016 को राज्य के शिक्षित युवाओं के लिए ''सक्षम युवा योजना'' नामक एक नई योजना शुरू की गई। इस योजना के तीन महत्त्वपूर्ण घटक – बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय हैं। योजना के तहत पंजीकृत पात्र स्नातकोत्तरों को 100 घंटे कार्य करने के एवज में 3000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता और 6000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा। इस प्रकार, वे

9,000 रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। पात्र आवेदक, जिन्हें मानद कार्य नहीं सौंपा गया है, वे सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत

कौशल प्रशिक्षण में भाग लेंगे। योजना के प्रति आवेदकों का गहरा रूझान रहा है। 28 फरवरी, 2017 तक कुल 18624 आवेदक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और इनमें से पात्र आवेदकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

आधारभूत संरचना

सड़कें

78. मजबूत बुनियादी ढांचा विकास का निर्माण खंड है। राज्य सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान राज्य में 8,600 किलोमीटर लम्बी सड़कों के मजबूतीकरण, सुधार, चौड़ा करने और निर्माण पर लगभग 4,700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कई वर्षों से अधर में लटका कुंडली–मानेसर–पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य शुरू किया गया है।

79. केन्द्र सरकार द्वारा अक्तूबर, 2014 से अब तक राज्य में कुल 505 किलोमीटर लम्बाई के चार नए राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त 469 किलोमीटर लम्बाई के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की घोषणा की गई है। इसके अलावा, 703 किलोमीटर लम्बी 11 राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

80. सितंबर 2014 से अब तक, हरियाणा राज्य से गुजरने वाली 906 किलोमीटर लम्बी नौ अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली–अमृतसर–कटड़ा एक्सप्रेसवे वाया जींद की स्वीकृति दी है, जो राज्य में विकास का एक नया कॉरिडोर खोलेगी।

81. हरियाणा सरकार की पहल पर, भारत सरकार ने रायमलिकपुर (राजस्थान सीमा) नारनौल–महेंद्रगढ़–चरखी दादरी–भिवानी कॉरिडोर को चार लेन की परियोजना में शामिल किया है। कॉरिडोर को पांच पैकेजों में विभाजित करके इस परियोजना को ईपीसी मोड में क्रियान्वित किया जाएगा। खरक से भिवानी और भिवानी से चरखी दादरी तक दो पैकेजों को पहले ही 517.54 करोड़ रुपये के साथ स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और शेष तीन पैकेज स्वीकृति प्रक्रिया के तहत हैं। इन पैकेजों पर वर्ष 2017–18 के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है।

82. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21ए के लिए 140 करोड़ रुपये की राशि से पिंजौर बाईपास के निर्माण की परियोजना स्वीकृत की है।

83. हरियाणा सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सेतु भारतम् योजना के तहत 346.69 करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8

आरओबी (जींद में 2 और झज्जर, अंबाला शहर, रेवाड़ी, लोहारू, कैथल और पिंजौर में एक–एक) स्वीकृत करवाए हैं।

रेलवे

84. हरियाणा प्रदेश में नई रेल लाइने बिछाने और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करके रेलवे नेटवर्क को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।

85. जून, 2016 में सोनीपत से जींद तक एक नई रेलवे लाइन लोगों को समर्पित की गई। रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है और इसके आगामी दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने इस रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए भूमि अधिगृहीत की है और रेलवे द्वारा इसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

86. हरियाणा सरकार ने रोहतक शहर में यातायात का दबाव कम करने के लिए 315 करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा रोहतक–गोहाना ट्रैक को ऊपर उठाने की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2017–18 के दौरान कार्य शुरू होने की संभावना है।

87. गत 27 महीनों के दौरान, 558 करोड़ रुपये की लागत से 13 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और 11 रेलवे अंडर ब्रिज(आरयूबी) का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस समय 21 आरओबी एवं आरयूबी का कार्य प्रगति पर है।

88. हरियाणा सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने हरियाणा में रेलवे सुविधाओं के निर्माण और सुधार के लिए 1217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जोकि गत वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है।

89. स्वीकृत परियोजनाओं में यमुनानगर से ज्योतिसर के बीच वाया कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर 55 किलोमीटर लंबी लाइन और कैथल एवं पटियाला के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शामिल है। जींद और हांसी के बीच एक नई लाइन को मंजूरी दी गई है, जिसका निर्माण 900 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। आने वाले समय में यह लाइन दक्षिणी एवं मध्य हरियाणा को उत्तरी हरियाणा एवं चण्डीगढ़ से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।

बिजली एवं सौर ऊर्जा

90. राज्य सरकार सभी ग्रामीण और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृत–संकल्प है, जिसके लिए ''म्हारा गांव, जगमग गांव'' योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, 165 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पंचकूला प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां सभी गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिल रही है।

91. लाइन हानियों को कम करने और ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने हेतु सरचार्ज माफी योजना–2016 और स्वैच्छिक घोषणा योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहे हैं और लगभग 1.08 लाख उपभोक्ताओं ने इस योजना में भाग लिया और लगभग 400 करोड़ रुपये के बिलों का निपटान हुआ है।

92. गत दो वर्षों के दौरान, सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के 73 सब–स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 228 सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 1300 किलोमीटर लम्बी बिजली लाइनें बिछाई गई हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा

93. सरकार ने कुछ श्रेणियों के भवनों के लिए सोलर रूफटॉप बिजली संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य किया है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध छतों का इस्तेमाल करने और उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों को कम करने में मदद करेगा। अब तक, राज्य में 45 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हुई हैं।

94. सरकार ने तीन चरणों में एक लाख सोलर आधारित होम सिस्टम प्रदान करने के लिए कुल 230 करोड़ रुपये की लागत से ''मनोहर ज्योति'' स्कीम शुरू की है।

95. राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 122 करोड़ रुपये की कुल लागत से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत केन्द्र और राज्य सरकार की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता से किसानों को 2 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के कुल 3050 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं।

96. मैं वर्ष 2017–18 में गैर–परंपरागत ऊर्जा विभाग के लिए 112.50 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ, जोकि गत वर्ष के 44.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान परिव्यय की तुलना में 154.18 प्रतिशत अधिक है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

97. सरकार बस्तियों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2016–17 में, 263 बस्तियों की समस्त आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2016 के अंत तक 157 बस्तियों को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में और 250 बस्तियों को यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है।

98. सरकार जल आपूर्ति के स्तर को 55/70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक बढ़ाने के लिए गांवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को मजबूत करने पर बल दे रही है। यह कार्य अतिरिक्त नलकूप स्थापित करके, मौजूदा नहर आधारित जल घरों के संवर्धन एवं सृजन, बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण और मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके किया जाएगा।

99. वर्तमान में, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से सात जिलों नामतः महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद और पलवल में 359 गांवों और 62 ढाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 750.29 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 11 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

100. राज्य के सभी कस्बों में पाइप आधारित जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है। 70 कस्बों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं जबकि पांच कस्बों में सीवरेज सुविधाएं बिछाने का कार्य प्रगति पर है। शेष पांच कस्बों में अधिसूचना के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा।

101. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वित्तीय सहायता के साथ चार कस्बों नामतः सोहना, नूंह, पटौदी और फारुख नगर में जलापूर्ति योजनाएं क्रियान्वित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले तीन शहरों पटौदी, पुन्हाना और हथीन में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

102. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत, सोनीपत और पानीपत शहरों में सीवरेज सुविधाओं के संवर्धन व सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटस के निर्माण के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रुपये और 129.51 करोड़ रुपये लागत की दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

103. मैं 2017–18 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3382.84 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 में 2906.52 करोड़ रुपये की तुलना में 16.39 प्रतिशत अधिक है।

परिवहन

104. सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षित और सक्षम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च, 2017 के अंत तक बस बेड़े में बसों की संख्या को 4200 तक बढ़ाए जाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संयोजिता में व्यापक सुधार आएगा। वर्ष 2017–18 में बस बेड़े में 5000 तक की वृद्धि होने की संभावना है। सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रति किलोमीटर स्कीम के आधार पर निजी बसों को किराये पर लेने पर भी विचार कर रही है। सरकार ने स्टेट कैरिज स्कीम 2017 अधिसूचित की है, जिससे निजी आप्रेटरों की बस उपलब्धता बढ़ने की संभावना है।

105. सरकार ने परिवहन विभाग में 2038 चालकों, 930 परिचालकों, 908 हैल्पर्स और स्टोर मैन के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

106. सरकार ने वर्ष 2016–17 में पायलट आधार पर अनेक नई पहल की हैं, जिनका वर्ष 2017–18 में बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। हरियाणा राज्य की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इनमें परस्पर (i) हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करना, (ii) पास जारी करने और अग्रिम बुकिंग सहित हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में हस्तचालित इलैक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन शुरू करना और (iii) सभी प्रमुख बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है।

107. वर्ष 2017–18 में, परिवहन विभाग के लिए 2459.70 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 में 2291.31 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 7.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

शहरी विकास

108. माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर, शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शहरों के रूपातंरण के लिए दो महत्त्वाकांक्षी योजनाएं नामतः ''स्मार्ट सिटी'' और ''अटल मिशन ऑफ रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफोरमेशन''(अमरूत) क्रियान्वित की जा रही हैं।

109. राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार के लिए अपना घर सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 882.50 करोड़ रुपये की लागत से 11,259 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति तैयार की गई है।

110. मैं शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3869.63 करोड़ रुपये और नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1103.95 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह परिव्यय संशोधित अनुमान 2016–17 में 3408.16 करोड़ रुपये की तुलना में 45.93 प्रतिशत अधिक है।

उद्योग

111. उद्योग आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके मद्देनजर, सरकार ने नई उद्यम प्रोत्साहन नीति तैयार और क्रियान्वित की है, जिससे राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बना है। गत एक वर्ष के दौरान 6.19 लाख करोड़ रुपये के निवेश के 407 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 86013 करोड़ रुपये के निवेश के 148 समझौते क्रियान्वयनाधीन हैं जिनसे राज्य में लगभग 1.60 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।

112. वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय, हरियाणा ''ईज़ ऑफ डुइंग बिजनैस'' के मामले में भारत वर्ष में 14वें स्थान पर था। बहरहाल, नई उद्यम प्रोत्साहन नीति की घोषणा के एक वर्ष के भीतर अब देश के अग्रणी राज्यों में और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है।

113. वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में 12,725 लघु और 266 मध्यम एवं बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। 16,780 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ इन उद्योगों ने 1.70 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है।

114. उद्यम या औद्योगिक मंजूरी प्रदान करने वाले सभी विभागों को संपर्क के एक बिंदु के साथ एक ही छत के नीचे लाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र से निवेशकों एवं उद्यमियों को पारदर्शी रूप से सहज और परेशानी मुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

115. मैं बजट अनुमान 2017–18 में, उद्योग और खनिज विभाग के लिए 399.88 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 366.99 करोड़ रुपये की तुलना में 8.96 प्रतिशत अधिक है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

116. हरियाणा राज्य ने अपने विज़न को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात (i) प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, (ii) मांग पर शासन एवं सेवाएं और (iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है।

117. सरकार और निजी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेशभर में आईसीटी आधारित अटल सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3600 से अधिक अटल सेवा केन्द्र और 134 ई–दिशा केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

118. राज्य में 2015 की आबादी के आधार पर शत–प्रतिशत आधार नामांकन हुआ है। वृद्धों, निशक्तों, स्थाई रूप से चलने–फिरने में असमर्थ(शय्याग्रस्त) नागरिकों के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से विशेष आधार नामांकन अभियान चलाया गया। शून्य से पांच वर्ष की आयु वर्ग के आधार नामांकन के लिए 400 टैबलेट खरीदे गये हैं और 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 500 आधार नामांकन किट्स खरीदी जा रही हैं।

119. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्मानित सदन को यह बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने ई–गवर्नेंस में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वे हैं :–

- नई पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पुरस्कार
- हरियाणा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(ई–ग्रास) के ई–स्टेम्पिंग एप्लीकेशन के साथ एकीकरण के लिए सीएसआई निहिलेंट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, 2016
- ई–ग्रास का ई–स्टेम्पिंग के साथ एकीकरण के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, 2016
- स्कॉच द्वारा ई–टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट
- समग्र वेब उपस्थिति के लिए हरियाणा स्टेट फार डिजिटल इंडिया–सिल्वर मैडल, एमईआईटीवाई, भारत सरकार

- गुरुग्राम जिला के राजस्व रिकार्ड का जीआईएस के साथ एकीकरण के जी–ट्रायंगुलेशन प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय ई–शासन पुरस्कार।

120. राज्य नागरिक डाटाबेस (एसआरडीबी) के तहत, आधार कोष के लिए लगभग 1.58 करोड़ नागरिकों का रिकॉर्ड एकत्रित किया गया है। विकसित नागरिक डाटा का इस्तेमाल भारत सरकार की परिकल्पना के अनुरूप लाभ प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। आंकड़ों के आदान–प्रदान के लिए विभिन्न विभागों की 29 ई–सेवाओं को एसआरडीबी के साथ एकीकृत किया गया है। एसआरडीबी की मदद से केरोसीन सब्सिडी, सामाजिक पेंशन और छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य के लिए काफी बचत हुई है।

121. मैं बजट अनुमान 2017–18 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 125.56 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित अनुमान 2016–17 के 88.69 करोड़ रुपये की तुलना में 41.57 प्रतिशत अधिक है।

पर्यटन और संस्कृति

13:00 बजे

122. राज्य सरकार भौतिक विकास की आवश्यकता के साथ–साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी सचेत है। इस दिशा में, राज्य ने दिसंबर, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया। सरकार सिंधु दर्शन, मानसरोवर यात्रा और गुरु दर्शन यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

123. भारत सरकार ने कृष्ण सर्किट के तहत कुरुक्षेत्र की पहचान एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में की है। इसके लिए राज्य द्वारा ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर का विकास किया जा रहा है और शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राज्य ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रेवाड़ी–महेंद्रगढ़–माधोपुर के लिए टूरिज़म इन्फ्रास्ट्रक्चर हैरिटेज सर्किट विकसित करने की पेशकश भी की है।

124. राज्य सरकार हरियाणा को एक फिल्म निर्माण–अनुकूल राज्य बनाने के लिए शीघ्र ही एक फिल्म नीति की घोषणा करेगी।

125. मैं 2017–18 में इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु पर्यटन के लिए 72.14 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं वृद्धों का कल्याण

126. आधुनिक भारत के महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जिन्होंने ''एकात्मक मानव दर्शन'' एवं ''अंत्योदय'' के सिद्धांत प्रतिपादित किये, का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। सरकार उनके सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने श्रमिकों, मजदूरों, गरीबों और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों, महिलाओं एवं वृद्धों के कल्याण एवं उत्थान के लिए नए कदम उठाए हैं।

127. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये की वित्तीय सहायता जबकि समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ''मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना'' के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये किया गया है।

128. डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसार 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

129. हरियाणा दिवस, 1 नवम्बर, 2016 से वृद्धों और दिव्यांगों तथा विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह की गई है। स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह की गई है।

130. मैं वर्ष 2017–18 के लिए, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 736.84 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 4875.47 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि 2016–17 के संशोधित अनुमान से क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत अधिक है।

महिला बाल विकास

131. राज्य में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समुदायों और सामाजिक संगठनों को एक ही मंच पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान सरकार के प्रयासों और बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप लिंगानुपात (जन्म के समय) में काफी सुधार हुआ है जो

2011 में केवल 830 की तुलना में दिसंबर, 2016 तक 900 के स्तर तक पहुंच गया है।

132. मैं 2017–18 में, महिला एवं बाल विकास के लिए 1247.24 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो कि संशोधित अनुमान 2016–17 में 1009.66 करोड़ रुपये की तुलना में 23.53 प्रतिशत अधिक है।

जिला योजना स्कीम

133. इस योजना के तहत जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़कों, सामुदायिक भवनों एवं खेल आदि के क्षेत्र में व्यापक विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। मैं 2017–18 के लिए इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कल्याण

134. हरियाणा राज्य के लगभग 2.50 लाख कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ 1 जनवरी, 2016 से देने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। सरकार ने स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे लगभग 2.25 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बजट 2016–17 में पहले ही पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

135. हरियाणा ने अपने पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की शुरूआत की है। स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर, सरकार ने होम गार्ड कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 572 रुपये प्रति दिन किया है, जो पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर है और इससे 5000 होम गार्ड लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11,000 सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन भी 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। सरकार ने 1 जनवरी, 2017 से अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इन वृद्धियों से सरकारी खजाने पर लगभग 2500 करोड़ रुपये वार्षिक का कुल वित्तीय भार पड़ेगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए नया विभाग

136. यह गर्व की बात है कि देश में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। राज्य सरकार रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा उनके ऋणी रहेंगे।

बहरहाल, उनके बलिदान के सम्मान और उनके प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के उद्देश्य से, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र ''सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग'' स्थापित किया गया है। शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में पढ़ रहे कैडेट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष की गई है।

137. अम्बाला में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है, जो युवाओं में सर्वोच्च बलिदान और सेवा की भावना जागृत करेगा।

138. सरकार ने वित्त वर्ष 2017–18 से भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों और अर्धसैन्य बलों के आश्रितों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, बैंकिंग सेवाओं जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोर्सों की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

केरोसीन मुक्त राज्य

139. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना 2011 सर्वेक्षण के आधार पर बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसे बीपीएल परिवारों को 1,600 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

140. प्रथम चरण में 1 नवंबर, 2016 तक आठ जिलों नामतः अम्बाला, गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकुला और यमुनानगर को केरोसीन मुक्त किया गया है और 31 मार्च, 2017 तक समस्त राज्य को केरोसीन मुक्त बनाने का लक्ष्य है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

141. लोगों विशेषकर, युवाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के सहयोग से सोनीपत में एक साईंस सिटी और अम्बाला में एक सब रीज़नल साईंस सेंटर स्थापित करने की योजना है। मैं वर्ष 2017–18 में इस कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्तु एवं सेवा कर

142. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में एक प्रमुख कराधान सुधार है, जोकि एक राष्ट्रव्यापी आईटी प्रेरित समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है और इसके 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की संभावना है। यह समान कराधान कानून देशभर में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को परेशानीमुक्त बनाएगा। यह कर सुधार ''एक राष्ट्र एक कर'' की अवधारणा को भी साकार करेगा।

143. राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार जीएसटी कानून बनाने के लिए जीएसटी परिषद् के साथ सक्रिय रूप से सम्पर्क में रही है। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी की अध्यक्षता में गठित जीएसटी परिषद् को सभी विवादास्पद मुद्दों पर सर्वसम्मति से प्रगतिशील निर्णय पर पहुंचने के लिए बधाई देता हूँ। हरियाणा प्रदेश जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए आईटी आधारभूत संरचना के विकास के मामले में मॉडल–। राज्य है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आवश्यक सॉफ्टवेयर के विकास और हार्डवेयर के नियोजन के लिए पहले ही एक सिस्टम इंटिग्रेटर को नियुक्त कर लिया है। विभाग के सभी अधिकारियों को जीएसटी प्रावधानों के संबंध में उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में, राज्य में वैट के तहत मौजूदा डीलरों को जीएसटी के तहत लाने की प्रक्रिया चल रही है।

144. वित्त वर्ष 2017–18 की प्रथम तिमाही में वैट से लगभग 8500 करोड़ रुपये का राजस्व और दूसरी से चौथी तिमाही में जीएसटी से लगभग 22000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है, जोकि 2016–17 के संशोधित अनुमान पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, राज्य आबकारी शुल्क से 6100 करोड़ रुपये, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन फीस से 3900 करोड़ रुपये और वाहनों पर कर से 2400 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की सम्भावना है।

कर प्रस्ताव

145. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मेरा वित्त वर्ष 2017–18 के इन बजट अनुमानों में हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एचवीएटी) अधिनियम, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में कोई बदलाव करने या कोई नया कर लागू करने के प्रस्ताव का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में, राज्य सरकार ने बायो डीजल (बी–100) और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में इस्तेमाल होने वाले सोलर उपकरणों एवं कलपुर्जों को वैट से छूट देकर कर मुक्त करने का निर्णय लिया है।

क्षेत्रवार आवंटन का पुनः अवलोकन

146. माननीय उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं वित्त वर्ष 2017–18 के लिए क्षेत्रवार आवंटन के बारे बताना चाहूंगा। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों (सिंचाई, सहकारिता और ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी सहित) को 12,784.72 करोड़ रुपये मिलने प्रस्तावित हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 4963.09 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। शिक्षा क्षेत्र (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, खेल, कला और संस्कृति सहित) के लिए 15546.65 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3839.90 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग एवं खनिज विकास के लिए 399.88 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 6859.55 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बिजली क्षेत्र के लिए 12,685.71 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3382.84 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़ रुपये और जिला योजना के लिए 400 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। परिवहन क्षेत्र के लिए 2549.81 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव है। भवन एवं सड़क क्षेत्र के लिए 3827.70 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। **(इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)**

147. किसी भी प्रयास की सफलता समाज के वंचित वर्गों के लिए उपलब्ध करवाए गए लाभों से आंकी जाती है। मैंने 2017–18 में एससीएसपी घटक के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से 7230 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है जोकि विकासात्मक योजनाओं के 35885 करोड़ रुपये के परिव्यय का 20.15 प्रतिशत है।

148. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ग्रामीण विकास के प्रति एक सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना एक अन्य प्राथमिकता है।

निष्कर्ष

149. माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय मैंने ''सबका साथ–सबका विकास'' के सिद्धान्त के अनुसार हमारे प्रगतिशील राज्य के समाज के सभी वर्गों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया है। कहने की आवश्यकता नहीं की, आम जनता के लिए विकास के एजेंडे के मामले में सबको एक साथ लेकर चलना वर्तमान सरकार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मैं इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों का मेरा बजट अभिभाषण बड़े ध्यान व धैर्य से सुनने के लिए तथा आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, आप सबसे हरियाणा को चहुंमुखी विकास, समृद्धि और लोगों की भलाई के मामले में नई ऊचाइयों पर ले जाने के लिए राजनैतिक एवं वैचारिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर इस पर चर्चा एवं विचार–विमर्श करने और मेरे बजट प्रस्ताव को अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ।

150. मैं यह आशा करता हूँ कि यह बजट प्रस्ताव आचार्य चाणक्य द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' में लोक कल्याणकारी राज्य के सूत्र पर आधारित होकर हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के सुख एवं कल्याण का कारण बनेंगे। यह सूत्र इस प्रकार है :

सुखस्य मूलं धर्मः
धर्मस्य मूलं अर्थः
अर्थस्य मूलं राज्यं
राज्यस्य मूलं इन्द्रिय जयः
इन्द्रियाजयस्य मूलं विनयः
विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवः

(सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल सुराज है, सुराज का मूल इन्द्रिय विजय है, इन्द्रीय विजय का मूल विनय है और विनय का मूल वृद्धों एवं आश्रितों की सेवा है।)

151. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ अब मैं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों को इस सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

वंदे मातरम् !

जय हिन्द!

.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 07 मार्च, 2017 प्रातः 10.00 बजे (प्रथम बैठक) तक के लिए *स्थगित किया जाता है।

* 13.21 बजे

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 07 मार्च, 2017 प्रातः 10.00 बजे (प्रथम बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई।)